साध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा ...!! "

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–184 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 23 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

आर्द्रभूमि संरक्षण और समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण, सरगुजा की आर्द्रभूमि में फिर दिखा राष्ट्रीय गौरव पक्षी सारस क्रेन

कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन के जोड़े का महत्वपूर्ण अवलोकन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-सरगुजा

छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की आर्द्रभूमियों में राष्ट्रीय गौरव पक्षी और दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी 'सारस क्रेन' का दिखना पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से बेहद सुखद खबर है। छत्तीसगढ़ में इन पक्षियों की संख्या बहुत कम बची है, इसलिए इनका किसी स्थानीय जलाशय या वेटलैंड में दिखाई देना एक महत्वपूर्ण घटना है। पक्षी 'सारस क्रेन' जीवनभर के लिए अपना एक ही साथी चुनते हैं। भारतीय संस्कृति में इन्हें प्रेम और अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है।

छत्तीसगढ़ में आर्द्रभूमि और पक्षी जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सरगुजा जिले से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। सरगुजा वनमंडल के लखनपुर परिक्षेत्र स्थित कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन के एक जोड़े का सफलतापूर्वक अवलोकन किया गया है। यह महत्वपूर्ण अवलोकन वनमंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत के मार्गदर्शन में चल रही नियमित निगरानी के दौरान दर्ज किया गया। क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग तकनीकी सहायक धनीराम और बीट गार्ड राजेंद्र खुजूर द्वारा की जा रही है। उनके प्रयासों से सारस क्रेन के जोड़े की यह महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की जा सकी।

आर्द्रभूमि के स्वस्थ होने का संकेत है सारस क्रेन : सारस क्रेन भारत के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक है और विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। किसी आर्द्रभूमि में इसकी उपस्थिति उस क्षेत्र के स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है। विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सारस क्रेन के प्रमाणित और नियमित अवलोकन वतर्मान में सरगुजा क्षेत्र से ही प्राप्त हो रहे हैं। इससे सरगुजा की आर्द्रभूमियों के संरक्षण महत्व को और मजबूती मिलती है।

वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड : कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन के जोड़े का अवलोकन राज्य की आर्द्रभूमि पक्षी विविधता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह रिकॉर्ड क्षेत्र की बेहतर पारिस्थितिक स्थिति और आर्द्रभूमि संरक्षण के सकारात्मक परिणामों को भी दर्शाता है। यह अवलोकन भविष्य में पक्षी विविधता के वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण योजनाओं और आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

सारस क्रेन का अवलोकन सरगुजा की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण का प्रयास : वन विभाग ने स्थानीय नागरिकों, पक्षी प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों से आर्द्रभूमियों एवं वन्यजीवों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। विभाग ने लोगों से ऐसे महत्वपूर्ण पक्षियों के अवलोकन की जानकारी वन विभाग को देने का आग्रह किया है, ताकि उनके संरक्षण और वैज्ञानिक अभिलेखीकरण को और मजबूत किया जा सके। कुवांरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में सारस क्रेन का यह अवलोकन सरगुजा की समृद्ध प्राकृतिक विरासत और आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सफलता का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

बरसते पानी में कांग्रेसियों ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और राहुल गांधी की हिरासत का विरोध, पुलिस से झड़प

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नीट पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को चंदूलाल चंद्राकार चौक, सुपेला में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। बरसते पानी के बावजूद कांग्रेसियों ने "मोदी सरकार शर्म करो", "शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो" और "भाजपा सरकार निकम्मी है" के नारे लगाए।

पुलिस से हुई झूमा-झटकी : पुतला दहन की सूचना पर पहले से ही चौक पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात थे। जैसे ही कांग्रेसी पुतला लेकर पहुंचे, पुलिस ने उसे छीनने का प्रयास किया। दोनों पक्षों के बीच करीब 15 मिनट तक झूमा-झटकी चली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतले में आग लगा दी। कुछ देर बाद पुलिस ने जलते पुतले को कब्जे में लेकर आग बुझाई। इस दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया।

'यह अमानवीय है' : पुतला दहन के बाद चंद्राकर ने कहा कि जंतर-मंतर से पैदल मार्च कर रहे छात्र-छात्राओं पर पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया वह अमानवीय है। प्रदर्शन में छात्रों के साथ उनके माता-पिता भी शामिल थे। उन्होंने कहा, "हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री निवास के समक्ष धरना दिया। उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। भाजपा सरकार को केंद्र से हटाए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे।"

चंद्राकर ने आरोप लगाया कि एक दिन पहले लोकसभा भवन के सामने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से पूरा देश उद्वेलित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने भी इस दमन के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध किया है।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद : प्रदर्शन में रिसाली महापौर शशि सिन्हा, केशव बंछोर, गिरवर बंटी साहू, ब्रजमोहन सिंह, इरफान खान, नरसिंह नाथ, जी राजू, दिनेश पटेल, मोहम्मद रफीक, संदीप निरंकारी, अरुण सिसोदिया, राजेश चौधरी, विनोद यादव, रामेश्वरी गायकवाड़, इतवारी देवांगन, जागेश्वरी साहू, मनीष शुक्ला, अनीशा बघेल, पिंकी वर्मा, सुरेंद्र वाघमारे सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

'युवाओं पर कार्रवाई न हो तो मैं अनशन तोड़ दूंगा' : वांगचुक का सरकार को पत्र

25वें दिन अस्पताल से जारी किया वीडियो, जेपी नड्डा-जितेंद्र सिंह ने की मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में 25 दिन से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने नई शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदर्शनकारी युवाओं पर कार्रवाई नहीं होगी तो वे अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं।

मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक ने अनशन के 25वें दिन वीडियो जारी कर कहा, 'मैं भी जीना चाहता हूं। सरकार ने सुसाइड करने वाले बच्चों के परिवारों को मुआवजा और संसद में चर्चा का भरोसा दिया है। इसी भरोसे पर मैं अनशन खत्म करने को तैयार हूं।'

नड्डा-डॉ. सिंह की मुलाकात

मंगलवार रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मिले। सूत्रों के अनुसार सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार युवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी और संसद में पूरे मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। वांगचुक के इस रुख के बाद 65 सांसदों और विभिन्न दलों के नेताओं ने भी उनसे अनशन तोड़ने की अपील की है।

विपक्ष को गेट पर रोका, दिल्ली में धरना

इसी बीच आप सांसद संजय सिंह सहित 15 विपक्षी सांसद वांगचुक से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने कहा कि सिर्फ परिजनों को ही मुलाकात की अनुमति है। विरोध में सांसद अस्पताल गेट पर ही धरने पर बैठ गए। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस तैनात है।

संसद में तीखी नोकझोंक

बुधवार को संसद में भी पेपर लीक का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "10 साल में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन एक भी दोषी साबित नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।"

जवाब में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "राहुल ने चुनिंदा राज्य उठाए। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल और कर्नाटक में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकारों में हुए पेपर लीक का जिक्र क्यों नहीं किया? उनका मकसद छात्र कल्याण नहीं, राजनीति है।" नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में चर्चा को तैयार है, विपक्ष तय करे कितने घंटे चर्चा करनी है।

देशभर में आंदोलन की गूंज

आंदोलन की आंच राज्यों तक पहुंच गई।
- **पटना:** 7 घंटे तक बवाल। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ ने महिला पुलिसकर्मी को चाकू मार दिया और भाजपा विधायकों की गाड़ी पर हमला किया।
- **हैदराबाद:** भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, महिला पुलिसकर्मी सहित 2 घायल।
- **बेंगलुरु:** भाजपा विधायक बीपी हरीश पर अंडे फेंके गए।
- **मुंबई:** प्रदर्शन के दौरान एक युवती पुलिस की बस के आगे अड़ गई।

देर रात जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पर फिर झड़प हुई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी। 2 एसीपी सहित 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने आंसू गैस चलाई और इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ की 20 कंपनियां वायुसेना के विमानों से दिल्ली लाई गईं और 16 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए।

हाईकोर्ट का आदेश : सारा वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखो

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने सीसीटीवी फुटेज और घटना के सभी वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

सीजेआई नेता सौरव दास ने कहा, "वार्ता मंत्री के घर नहीं, जंतर-मंतर पर होगी। सरकार तभी बुलाए जब मांगें माननी हों।" अब सबकी नजर वांगचुक के अगले कदम और संसद में होने वाली चर्चा पर टिकी है।

विशेष विश्लेषण

राहुल-अखिलेश की जुगलबंदी के आगे बैकफुट पर सरकार

आलोक तिवारी/ नईदिल्ली

नीट-पेपर लीक पर संसद से सड़क तक घमासान, छात्र आंदोलन ने बदली राजनीति की धारा

संसद के मानसून सत्र में NEET पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। 2024 के आम चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एकजुट रणनीति ने सत्ता पक्ष को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। नतीजाः सरकार को पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए मजबूर होना पड़ा।

विपक्ष की "तीन शर्तें", सरकार पर सीधा दबाव

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। उनकी तीन गैर-समझौतावादी मांगें हैं
* शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
* छात्रों पर ज्यादती करने वालों पर कार्रवाई
* प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक माफी

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की और कहा कि जब तक मंत्री पद पर बने रहेंगे, निष्पक्ष जांच संभव नहीं। विरोध के तौर पर कांग्रेस और सपा सांसद बांहों पर काली पट्टी और काले अंगवस्त्र पहनकर सदन में पहुंचे। "पहले इस्तीफा, फिर चर्चा" का नारा पूरे सत्र में गूंजता रहा।

राहुल-अखिलेश की नई केमिस्ट्री ने बदला खेल

इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सामरिक एकजुटता। अखिलेश ने शुरुआत से ही इस मुद्दे को भुनाया। उन्होंने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव को जंतर-मंतर भेजा और सड़क पर पार्टी कार्यकर्ताओं को उतारा। इसके बाद राहुल गांधी के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में तय हुआ कि पेपर लीक और युवा नाराजगी को संसद का मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा। इस जुगलबंदी का असर तुरंत दिखा। जब सदन में आवाज नहीं सुनी गई तो दोनों नेता प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए निकल पड़े। अखिलेश ने सदन में कहा, "हम मजबूरी में प्रधानमंत्री आवास पर गए। अगर संसद में बात सुन ली जाती तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।" छत्रसाल स्टेडियम में जब राहुल को हिरासत में रखा गया, तो अखिलेश बस लेकर अपने सांसदों के साथ वहां पहुंच गए। यह तस्वीर 2024 के बाद विपक्ष की सबसे मजबूत एकता के रूप में देखी जा रही है।

सड़क से संसद तक-आंदोलन का राष्ट्रीयकरण

जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। दिल्ली में सोनम वांगचुक का 25वें दिन का अनशन, पटना में 7 घंटे का बवाल और लाठीचार्ज, जयपुर-लखनऊ-बेंगलुरु-चेन्नई में छात्र संगठनों का सड़क उतरना — सरकार के लिए यह सिर्फ शैक्षणिक मुद्दा नहीं रह गया है। छात्र अब केवल NEET की बात नहीं कर रहे, वे रोजगार, पारदशिर्ता और युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि यह आंदोलन आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है।

सरकार बैकफुट पर क्यों ?

पहले सरकार इस मुद्दे को "राज्य सरकारों की जिम्मेदारी" बताकर टाल रही थी। लेकिन राहुल-अखिलेश के संयुक्त दबाव, संसद में गतिरोध और सड़क पर बढ़ते प्रदर्शन के बाद उसे चर्चा के लिए हामी भरनी पड़ी। भाजपा की रणनीति अब "पलटवार" पर है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासित राज्यों में हुए पेपर लीक गिनाकर जवाब दिया। लेकिन सड़क पर जिस तरह युवा उतरे हैं, उससे स्पष्ट है कि यह जवाब पर्याप्त नहीं है।

आगे क्या ?

यह लड़ाई अब केवल ठएएळ तक सीमित नहीं है। यह 2024 के चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष की नई राजनीतिक प्रयोगशाला है। राहुल की आक्रामकता और अखिलेश की जमीनी पकड़ का मिश्रण यदि बना रहा, तो आने वाले महीनों में यह गठबंधन सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

छात्रों की मांग, विपक्ष का दबाव और सरकार की मजबूरी — तीनों के बीच फंसा यह मुद्दा अब तय करेगा कि संसद में बहस होगी या सड़क पर संग्राम और तेज होगा।

एक बात तय हैः युवाओं का मुद्दा अब चुनावी मुद्दा बन चुका है और राहुल-अखिलेश की जोड़ी ने इसे राष्ट्रीय एजेंडा बना दिया है।

राजधानी में रैली के दौरान पत्थरबाजी, 16 पुलिस जवान हुए घायल

कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राजधानी में मंगलवार को एक रैली के दौरान कानून-व्यवस्था संभाल रहे पुलिस बल पर पत्थर और बोतलें फेंके जाने से अव्यवस्था फैल गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात 16 पुलिस जवान घायल हो गए। घायलों में एक महिला आरक्षक भी शामिल है। दो जवानों को गंभीर चोटें आई हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रैली को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने अचानक पत्थर और बोतलें फेंकना शुरू कर दिया।

कमिश्नर ने लिया उपचार का जायजा : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भर्ती जवानों से मुलाकात कर हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य एवं उपचार की विस्तृत जानकारी ली। कमिश्नर ने सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए और जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

घायल जवान कलेश्वर वर्मा ने बताया कि बैरिकेडिंग के दौरान भीड़ के बीच फंस जाने से उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। प्रशिक्षु उप निरीक्षक देवराज सिंह के सिर पर बोतल लगने से गंभीर चोट आई है। उनका उपचार चिकित्सकों की निगरानी में जारी है। अन्य घायल आरक्षकों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

इस दौरान पुलिस उपायुक्त मध्य तारकेश्वर पटेल, एसीपी नीलेश द्विवेदी, टीआई राजेश मरई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

खास खबर

कम टैक्स के चक्कर में अधूरी जानकारी के साथ न भरें ITR : सीए पीयूष जैन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

कहा रिटर्न ऐसा हो, जिसे वर्षों बाद भी दस्तावेजों के आधार पर समझाया जा सके

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय केवल टैक्स कम करने पर ध्यान देना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। अधूरी जानकारी और गलत सलाह के आधार पर भरा गया रिटर्न बाद में नोटिस, ब्याज, पेनाल्टी और लंबे कर-विवाद की वजह बन सकता है। इसलिए करदाताओं को ऐसा रिटर्न दाखिल करना चाहिए, जिसकी प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी को तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर वर्षों बाद भी समझाया जा सके। यह बात भिलाई सीए ब्रांच के पूर्व चेयरमैन एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पीयूष जैन ने कही। उन्होंने बताया कि आयकर रिटर्न अब केवल सालभर की आय बताने वाला फॉर्म नहीं है, बल्कि यह करदाता की पूरी वित्तीय स्थिति और विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बन चुका है।

सीए जैन ने कहा कि कई करदाता रिटर्न बनवाते समय अपने कंसल्टेंट को सभी बैंक खातों, नकद लेन-देन, निवेश, ऋण, प्रॉपर्टी खरीद, कैपिटल गेन और कृषि आय की पूरी जानकारी नहीं देते। कुछ मामलों में कंसल्टेंट भी उपलब्ध सीमित जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में रिटर्न तैयार कर देता है। उस समय रिटर्न दाखिल हो जाता है, लेकिन बाद में अलग-अलग वित्तीय लेन-देन सामने आने पर उसे समझाना कठिन हो सकता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में आयकर विभाग को PAN, Aadhaar, AIS, Form 26AS, TDS, TCS, बैंकिंग प्रणाली, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं से वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिलती रहती है। कोई लेन-देन वतर्मान अक्र में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी जानकारी भविष्य में विभाग तक नहीं पहुंचेगी।

44AD में केवल 6 या 8 प्रतिशत दिखाना पर्याप्त नहीं : सीए पीयूष जैन ने बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए लागू Section 44AD का उद्देश्य अकाउंटिंग और ऑडिट संबंधी अनुपालन को आसान बनाना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल टर्नओवर पर 6 या 8 प्रतिशत लाभ दिखाकर रिटर्न दाखिल कर दिया जाए। रिटर्न तैयार करने से पहले बैंक में आए कुल क्रेडिट, नकद जमा, वढकप्राप्तियां, GST टर्नओवर, बड़े निवेश, ऋण संबंधी लेन-देन, घरेलू खर्च और पूंजी की स्थिति का व्यापक मिलान आवश्यक है। यदि घोषित आय और वास्तविक वित्तीय गतिविधियों में बड़ा अंतर दिखाई देता है, तो भविष्य में निवेश के स्रोत को लेकर प्रश्न उठ सकते हैं। उन्होंने कहा, “Section 44AD करदाता को बुक्स ऑफ अकाउंट की जटिलता से राहत देता है, वास्तविक तथ्यों से नहीं।

डॉक्टर और प्रोफेशनल भी बरतें सावधानी : उन्होंने Section 44ADA के अंतर्गत रिटर्न भरने वाले डॉक्टरों और अन्य प्रोफेशनल्स को भी सावधानी बरतने की सलाह दी। केवल ग्रॉस रिसीप्ट की 50 प्रतिशत आय घोषित कर देना हर स्थिति में पर्याप्त नहीं होता। यदि किसी प्रोफेशनल ने उसी वर्ष म्यूचुअल फंड, एफडी, जमीन या अन्य संपत्तियों में बड़ा निवेश किया है, तो निवेश के स्रोत का उचित विवरण होना जरूरी है। पुराने निवेश, बचत, ऋण, उपहार या संपत्ति की बिक्री से धन प्राप्त हुआ हो सकता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहना चाहिए।

जमीन होना कृषि आय का प्रमाण नहीं : कृषि आय के संबंध में सीए जैन ने कहा कि केवल जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर अनुमानित आय नहीं दर्शानी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि वास्तव में खेती हुई या नहीं, कौन-सी फसल ली गई, भूमि सिंचित थी या असिंचित, फसल कहां बेची गई और बिक्री अथवा बैंकिंग से संबंधित क्या प्रमाण उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, कृषि आय खेत देखकर नहीं, खेती देखकर तय होती है।

AIS जानकारी देता है, अंतिम निर्णय नहीं : सीए जैन ने कहा कि अक्र रिटर्न तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन उसे अंतिम सत्य मानना भी गलत है। बोनस शेयर, विरासत में मिली संपत्ति, ऑफ-मार्केट ट्रांसफर, गिफ्ट, फैमिली सेटलमेंट, डिमर्जर, अमलगमेशन और पुराने मालिक की लागत जैसे मामलों में दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों की अलग से जांच आवश्यक होती है। उन्होंने कहा, “AIS डेटा देता है, लेकिन सही टैक्स ट्रीटमेंट का निर्णय दस्तावेजों और कानून के आधार पर लिया जाता है।

करदाता और कंसल्टेंट दोनों की साझा जिम्मेदारी : सीए पीयूष जैन ने कहा कि सही रिटर्न तैयार करना करदाता और टैक्स कंसल्टेंट दोनों की साझा जिम्मेदारी है। करदाता को सभी आय स्रोतों, बैंक खातों, निवेश, ऋण, उपहार, संपत्ति लेन-देन, विदेशी संपत्तियों, कृषि आय और बड़े नकद लेन-देन की जानकारी समय पर देनी चाहिए। कंसल्टेंट को भी बैंक स्टेटमेंट, AIS, Form 26AS, GST आंकड़ों, निवेश और पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के बीच तार्किक सामंजस्य देखना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर करदाता को संभावित जोखिम के बारे में लिखित रूप से जानकारी दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी टैक्स प्लानिंग वह नहीं है, जिसमें हर हाल में सबसे कम टैक्स दिखाया जाए। बेहतर टैक्स प्लानिंग वह है, जिसमें कानून का पालन करते हुए ऐसा रिटर्न तैयार हो, जिसे भविष्य में भी पूरे विश्वास के साथ सही साबित किया जा सके। रिटर्न ऐसा भरिए जिसे विभाग से पहले आप स्वयं पढ़कर प्रत्येक आंकड़े का आधार बता सकें। कम टैक्स दिखाना सफलता नहीं है, सही और स्पष्ट रिटर्न दाखिल करना वास्तविक सफलता है।

शिक्षामंत्री यादव ने विद्यार्थियों, पालकों और शिक्षकों से किये संवाद

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के बोरसीभांठा, पोटिया-झुग्गीपारा एवं पद्मनाभपुर स्थित शासकीय विद्यालयों में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों में शामिल होकर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाये एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किये। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को गणवेश एवं जूते वितरित किए तथा विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी किये।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि नया शिक्षा सत्र बच्चों के जीवन में नए सपनों, नई ऊर्जा और नए अवसरों का प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों में बेहतर अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और आधुनिक संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा के महत्व को बताया तथा कहा कि तकनीक आधारित शिक्षण से विषयों को समझना अधिक सरल होगा और बच्चे भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा मंत्री श्री यादव कक्षाओं में भी पहुंचे और बच्चों के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई, पसंदीदा विषयों तथा भविष्य के सपनों पर आत्मीय चर्चा की। बच्चों के उत्साह, आत्मविश्वास और सीखने की जिज्ञासा की सराहना करते हुए उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने एवं नियमित रूप से विद्यालय आने का संदेश दिये। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में पालकगण उपस्थित रहे।

अतिथि शिक्षक संघ से आंदोलन समाप्त करने का किया आग्रह

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी विभिन्न मांगों पर चर्चा की। अतिथि शिक्षक संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा अतिथि शिक्षकों के संविलियन/समायोजन और ग्रीष्म अवधि का मानदेय प्रदान करने समान कार्य- समान वेतन के तहत व्याख्याता पद के मूल वेतनमान का लाभ देने तथा शासकीय कमर्चारियों के समान अवकाश की पात्रता के तहत विभिन्न मांगे रखी गई।प्रतिनिधिमंडल के साथ सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। अतिथि शिक्षकों की समस्त मांगो एवं समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक और संवेदनशीलता के साथ विचार किए जाने के संबंध में मंत्री श्री यादव दवारा आश्वासन दिया गया। साथ ही प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों के प्रति सदैव संवेदनशील है और उनके जायज अधिकारों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक संघ द्वारा विगत कुछ दिनों से संचालित धरना प्रदर्शन को समाप्त किए जाने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह किया। इसके बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने भी अतिथि शिक्षक संघ से धरना समाप्त कर स्थल मुक्त करने की अपील की।

भिलाई नगर निगम आयुक्त सुरुचि सिंह का आर्टकॉम ने पौधा देकर किया स्वागत

नए भवनों में एक पेड़ और वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने का सुझाव

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

पर्यावरण संस्था 'आर्टकॉम, हर आंगन एक पेड़' के पदाधिकारियों ने नगर पालिका निगम भिलाई की नवनियुक्त आयुक्त सुरुचि सिंह का स्वागत पौधा भेंट कर किया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक करमजीत सिंह, अध्यक्ष गुरुनाम सिंह, मीडिया सलाहकार अमिताभ भट्टाचार्य, मेघा कौर और संतोष जायसवाल उपस्थित रहे। बैठक में संस्था ने पिछले 8 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। आयुक्त ने संस्था के कार्यों की सराहना की।

नए निर्माण में हरियाली और जल संरक्षण पर जोर

संस्था के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने आयुक्त को सुझाव दिया कि जब भी घरों के निर्माण की अनुमति दी जाए तो उसमें आंगन में एक पेड़ लगाना और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाए। आयुक्त सुरुचि सिंह ने इस सुझाव की प्रशंसा करते हुए इसे लागू करने का आश्वासन दिया। संरक्षक करमजीत सिंह ने कहा कि आयुक्त द्वारा पर्यावरण और जल संवर्धन की दिशा में शुरू की जाने वाली पहल आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आर्टकॉम, हर आंगन एक पेड़ ने निगम के साथ मिलकर आने वाले समय में पर्यावरण संबंधी अभियानों में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया।

आयुक्त ने विभिन्न जोनों का किया निरीक्षण, जलभराव और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरुचि सिंह ने निगम क्षेत्र के विभिन्न जोनों का निरीक्षण कर नागरिकों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जोन-1 नेहरू नगर स्थित बाम्बे आवास के पास डूबान क्षेत्र, जोन-2 रामनगर स्थित नवीन पानी टंकी तथा जोन-3 अंतर्गत दुर्गापारा स्थित तालाब का बारीकी से अवलोकन किया। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जलभराव, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आयुक्त ने सबसे पहले जोन-1 नेहरू नगर क्षेत्र में बाम्बे आवास के पास स्थित डूबान क्षेत्र का निरीक्षण किया। बरसात के दौरान अधिक बारिश होने पर यहां जलभराव की स्थिति निर्मित होने से नागरिकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए आयुक्त ने अधिकारियों से क्षेत्र की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए नालियों की नियमित सफाई कराई जाए। नालियों में कचरा, गाद एवं अन्य अवरोध जमा न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखने के साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात निगम आयुक्त ने जोन-2 रामनगर स्थित नवीन पानी टंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी टंकी की वतर्मान स्थिति एवं संचालन व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों से जानकारी ली। आयुक्त ने टंकी से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र के नागरिकों को नियमित एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आयुक्त ने कहा कि तालाब के आसपास गंदगी एवं कचरा जमा न होने दिया जाए तथा नागरिकों द्वारा तालाब के किनारे कचरा फेंकते पाए जाने पर तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता व्यवस्था की सतत निगरानी करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, अनिल सिंह, अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता श्वेता वर्मा, नितेश मेश्राम, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उप अभियंता पुरुषोत्तम सिन्हा, शंकर सुमन मरकाम, दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, बीरेन्द्र बंजारे एवं स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह, चुड़ामणी यादव सहित निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पीएम आवास के हितग्राहियों को बेटी की शादी पर मिलेगा नि :शुल्क गैस कनेक्शन, विधायक रिकेश सेन की एक और घोषणा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जनहित और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखकर लगातार नवाचारपूर्ण योजनाएं लागू कर रहे विधायक रिकेश सेन ने आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवारों में बेटियों का विवाह होने पर नवविवाहित दंपत्ति को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा प्रदान किया जाएगा। इस नई पहल का शुभारंभ 10 अगस्त से किया जाएगा।

विधायक रिकेश सेन का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटी के विवाह के बाद नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत सुविधाजनक और सम्मानजनक हो, यही इस योजना का उद्देश्य है। उनका मानना है कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन स्तर से भी जुड़ा हुआ है।

गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा में पिछले कुछ समय से विधायक रिकेश सेन लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। मात्र एक रुपये में चश्मा उपलब्ध कराने की योजना के माध्यम से हजारों लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मां-शिशु सुरक्षा कवच योजना के तहत नवजात शिशुओं और माताओं को आवश्यक सामग्री से युक्त सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और जरूरतमंद परिवारों की सहायता को लेकर विधानसभा क्षेत्र में लगातार नई पहलें की जा रही हैं, जिन्हें व्यापक जनसमर्थन भी मिल रहा है।

स्थानीय नागरिकों ने भी इस नई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि बिटिया के विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे नए परिवारों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक रसोई की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। लगातार जनहित, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से वैशाली नगर विधानसभा में विकास की नई कार्यशैली देखने को मिल रही है। विधायक रिकेश सेन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाना है। इसी सोच के साथ 10 अगस्त से शुरू होने वाली यह नई योजना भी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात साबित होने की उम्मीद है।

गुण्डिचा मंडप में संगीत संध्या की धूम, महाप्रभु ने दिए राज-राजेश्वर वेश में दर्शन

जय बजरंगी म्यूजिकल ग्रुप की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूमे

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जगन्नाथ समिति सेक्टर-4 के तत्वावधान में सेक्टर-10 स्थित भव्य गुण्डिचा मंडप में रथयात्रा महोत्सव के तहत प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार रात हुई संगीत संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्ति संगीत का आनंद लिया। इस अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी ने भक्तों को राज-राजेश्वर वेश में दर्शन दिए।

संगीत संध्या में "जय बजरंगी म्यूजिकल ग्रुप" के कलाकारों ने बेहतरीन भजन प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय कर दिया। सुश्री मधुस्मिता दीक्षित के नेतृत्व में समूह ने "जगन्नाथ जगन्नाथ, चका नैन, वो निलाचल वाले, तू ना संभले तो, हमें कौन संभाले" सहित उड़िया और हिंदी भजन गाए। भजनों की प्रस्तुति पर पूरा पंडाल झूम उठा और श्रद्धालु नाचने को मजबूर हो गए।

अतिथियों ने किया कलाकारों का सम्मान : कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएसएमई एसोसिएशन एवं दुर्ग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्रा रहे। उनके साथ समिति के अध्यक्ष वीरेन्द्र सतपथी और महासचिव सत्यवान नायक विशेष रूप से उपस्थित थे। अतिथियों ने गायक कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और संस्था को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। महासचिव सत्यवान नायक ने रथयात्रा के अंतर्गत आगे होने वाले बहुड़ा रथयात्रा और नीलाद्री विजय जैसे आयोजनों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संयोजन त्रिनाथ साहू ने किया।

आयोजन को सफल बनाने में इनका योगदान : इस उत्सव को सफल बनाने में वीरेन्द्र सतपथी, सत्यवान नायक सहित त्रिनाथ साहू, भीम स्वांई, अनाम नाहक, डी त्रिनाथ, बसंत प्रधान, बीसी बिस्वाल, वृंदावन स्वांई, कालू बेहेरा, सुशांत सतपथी, जगन्नाथ पटनायक, रंजन महापात्र, प्रकाश स्वांई, राजू बेहेरा, रवि स्वांई, कवि बिस्वाल, सीमांचल बेहरा, वी के होता, कैलाश पात्रो, बी के साहू और श्याम दलाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विशेष अभियान — स्कूल-कॉलेजों में सुरक्षा संवाद, हेल्पलाइन और अभिव्यक्ति ऐप की दी जानकारी,

महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए दुर्ग पुलिस का "पिंक पेट्रोलिंग अभियान" तेज

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सवोच्च प्राथमिकता देते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा जिले भर में "पिंक पेट्रोलिंग अभियान" निरंतर संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला पुलिस अधिकारियों और पिंक पेट्रोलिंग टीमों ने विभिन्न स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और छात्राओं से सीधा संवाद किया।

स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम

थाना खुर्सीपार क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्वामी आत्मानंद विद्यालय और श्रीराम चौक में छात्राओं को महिला हेल्पलाइन-1091, डायल-112 और "अभिव्यक्ति ऐप" के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें छेड़छाड़, पीछा करने या किसी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही स्कूल आने-जाने के मार्गों पर घूमने वाले असामाजिक तत्वों के संबंध में भी फीडबैक लिया गया।

थाना सुपेला क्षेत्र में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुपेला और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुपेला में छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों और सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया।

थाना पुलगांव क्षेत्र की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पुलगांव में छात्राओं और शिक्षकों को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराया गया और पिंक पेट्रोलिंग के उद्देश्य बताए गए।

थाना भिलाई नगर क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कैंप-2, केपीएस स्कूल, बरोडा टैंक स्कूल, शास्त्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, भिलाई भट्ठी पार्क और डीएवी पब्लिक स्कूल सहित कई स्थानों पर पेट्रोलिंग की गई। यहां छात्राओं, अभिभावकों और आम नागरिकों को महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

अभियान का उद्देश्य

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिंक पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित माहौल देना और अपराधों की रोकथाम करना है। टीमों ने विद्यालय परिसरों और छात्राओं के आवागमन मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया।

दुर्ग पुलिस ने महिलाओं, छात्राओं और अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने या साइबर अपराध की सूचना तुरंत डायल-112, महिला हेल्पलाइन-1091 या नजदीकी थाने पर दें। अभिव्यक्ति ऐप का अधिक से अधिक उपयोग कर सुरक्षित समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करें। अभियान में संबंधित थाना प्रभारी, महिला उप निरीक्षक, पिंक पेट्रोलिंग टीम और थाना स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही।

सेवा भाव, संवेदनशीलता और तार्किक निर्णय से निभाएं दायित्व – राज्यपाल रमेन डेका

राज्यपाल से प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने की सौजन्य मुलाकात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं, बल्कि आम जनता की सेवा का महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर का पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और ईमानदारी से निर्वहन करना प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि जहां चुनौतियां होती हैं, वहीं नए अवसर भी मौजूद होते हैं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करते हुए जनता के हित में निर्णय लिए जाने चाहिए।

राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों से चर्चा कर रहे थे। ये अधिकारी वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों ने अकादमी के महानिदेशक टीसी महावर के नेतृत्व में राज्यपाल से सौजन्य भेंट की।

राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक निर्णय में मानवीय संवेदनाओं का भी समावेश होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य में ह्यूमन टच होना आवश्यक है, ताकि शासन की योजनाओं और निणर्यो का लाभ वास्तविक रूप से आम नागरिकों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता से नियमित संवाद करना चाहिए, क्षेत्र का सतत भ्रमण करना चाहिए और लोगों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कार्य संभव हो, उसे प्राथमिकता के साथ पूरा करें और यदि किसी कारणवश कोई कार्य संभव नहीं है तो उसकी स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी संबंधित व्यक्ति को अवश्य दें। इससे प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तार्किक सोच और विवेकपूर्ण निष्कर्ष अत्यंत आवश्यक हैं। तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना ही एक सक्षम अधिकारी की पहचान है। उन्होंने कहा कि जनता को न्याय दिलाना लोक सेवक का प्रथम कर्तव्य है और प्रत्येक अधिकारी को इस भावना के साथ कार्य करना चाहिए।

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे युवा हैं और उनके कंधों पर भविष्य के प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने कार्यों के माध्यम से सुशासन, पारदर्शिता और जनविश्वास को मजबूत करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको छत्तीसगढ़ जैसे शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में सेवा करने का अवसर मिला है। यहां के लोगों में सेवा, सहयोग और आत्मीयता की भावना अत्यंत प्रबल है। इस विश्वास और अपनत्व को बनाए रखते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही एक सफल प्रशासनिक अधिकारी की पहचान होगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी की प्रशिक्षण निदेशक श्रीमती मेनका प्रधान एवं प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे।

खास खबर

मुख्यमंत्री साय से लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात : 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर की तैयारियों पर हुई चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 18, 19 एवं 20 सितंबर को रायपुर में आयोजित होने वाले 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर की तैयारियों, उद्देश्यों एवं आयोजन की विस्तृत रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक आयोजन प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नई दिशा देने के साथ–साथ निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को भी गति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग–अनुकूल वातावरण तैयार करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा उद्यमियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय औद्योगिक समागम का आयोजन छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लघु उद्योग भारती लघु उद्यमियों का देश का सबसे बड़ा संगठन है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने तथा उद्योगों के बीच व्यवसायिक सहयोग (बी2बी) को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। रायपुर में आयोजित होने वाला 14वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर देशभर के उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों एवं तकनीकी संस्थानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां आधुनिक तकनीक, निवेश, विपणन, उद्योग–व्यापार सहयोग और व्यापार विस्तार के नए अवसर विकसित होंगे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा देने के साथ प्रदेश को राष्ट्रीय औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन से स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने, नई तकनीकों को अपनाने और व्यापार विस्तार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्त, संयुक्त महासचिव नरेश पारख, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समीर, प्रांत अध्यक्ष श्रीमती सीपी दुबे, पुरुषोत्तम पटेल, अनिल बाकलीवाल, श्रीमती तूलिका पांडे एवं प्रांजल सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

साहित्य सृजन संस्थान की 47वीं काव्य संध्या 26 को, साहित्य के साथ स्वास्थ्य व जीवनशैली पर होगी चर्चा

रायपुर, 22 जुलाई 2025। साहित्य सृजन संस्थान परिवार की 47वीं नियमित मासिक काव्य संध्या 26 जुलाई रविवार को अपराह्न 3 बजे से वृंदावन हॉल, सिविल लाइन्स में आयोजित की जाएगी।

संस्थान के अध्यक्ष वीर अजीत शर्मा ने बताया कि इस बार की काव्य संध्या विशेष रहेगी। इसमें बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, भिलाई, बागबाहरा, खरोरा, आरंग एवं राजधानी रायपुर के कवि और शायर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कोरबा की अनसुइया श्रीवास होंगी जो अपना काव्यपाठ प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 9 वर्षीय बालिका कुहुक अग्रवाल की प्रस्तुति रहेगी। कुहुक "कृष्ण की चेतावनी– महाभारत का सबसे बड़ा संदेश" विषय पर आकर्षक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी।

साहित्य के साथ स्वास्थ्य पर संवाद : इस बार काव्य संध्या में साहित्य के साथ स्वास्थ्य और जीवनशैली को भी जोड़ा गया है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डॉ. संजय अलंग "पेट क्यों निकलता है के ऐतिहासिक कारणों पर चर्चा" विषय पर व्याख्यान देंगे। वहीं क्छर हॉस्पिटल की डॉ. शिलिका लालवानी "मधुमेह, मोटापा एवं थायरॉइड" विषय पर जानकारी देंगी। आयोजकों के अनुसार साहित्य, स्वास्थ्य और जीवनशैली के समन्वय से यह काव्य संध्या आमजन के लिए अधिक उपयोगी और प्रेरणादायी होगी।

जनजातीय बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम बनेगा शबरी वाचनालय – राज्यपाल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

ाज्यपाल रमेन डेका ने वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा जनजातीय बालिकाओं में अध्ययन, ज्ञानार्जन एवं पठन–पाठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित शबरी वाचनालय का उद्घाटन किया। वाचनालय की स्थापना के लिए राज्यपाल द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शबरी वाचनालय एक दूरदर्शी पहल है, जो जनजातीय बालिकाओं के लिए अध्ययन, चिंतन, आत्मविकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त केंद्र बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां अध्ययन करने वाली बालिकाएं ज्ञान एवं शिक्षा के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगी। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाएंगी।

उन्होंने कहा कि शबरी कन्या आश्रम वर्षों से जनजातीय बालिकाओं को केवल आश्रय और शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रसेवा की भावना भी प्रदान कर रहा है। इसी का परिणाम है कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाली अनेक बालिकाएं आज शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण राज्य है। यहां की संस्कृति का संबंध रामायण काल की परंपराओं से है। उन्होंने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक समानताएं हैं तथा दोनों राज्यों की सांस्कृतिक धारा भगवान श्रीराम से जुड़ी हुई है। ऐसे गौरवशाली सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा होना हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय इंटरनेट और तकनीक का युग है। तेजी से बदलती जीवनशैली के बीच जीवन मूल्यों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार और समाज के प्रति संवेदनशीलता, संतोष और सकारात्मक सोच ही जीवन को सार्थक बनाती है। संतुष्ट व्यक्ति ही वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकता है। जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसलिए इसके प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ प्रांत विगत कई दशकों से जनजातीय समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन एवं सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का यह प्रयास वास्तव में प्रेरणादायी है। उन्होंने संस्था के संस्थापकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों के समर्पण भाव की सराहना करते हुए उनके सेवा कार्यों की प्रशंसा की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ वनवासी विकास समिति के अध्यक्ष उमेश कच्छप, सचिव अनुराग जैन, संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सहयोगी तथा शबरी कन्या आश्रम की छात्राएं उपस्थित थीं।

अवैध उर्वरक और कीटनाशक के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराने तथा नकली एवं अमानक उर्वरक–कीटनाशकों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत प्रदेशभर में कृषि विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्ग जिले में कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल ने ग्राम चिंगरी (अंडा) में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध अनुज्ञप्ति के उर्वरक एवं कीटनाशक का निर्माण, भंडारण और विक्रय किए जाने के मामले में दो गोदामों को सील कर भारी मात्रा में सामग्री जब्त की है।

उड़नदस्ता दल को ग्राम चिंगरी स्थित चन्द्राकर किराना स्टोर्स परिसर में अवैध रूप से जैव उत्प्रेरक एवं कीटनाशकों के निर्माण एवं भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी। निरीक्षण के दौरान गोदाम बंद मिला। गोदाम के किरायेदार वरुण त्रिपाठी को मौके पर बुलाकर निरीक्षण में सहयोग करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके असहयोगात्मक रवैये के कारण मकान मालिक, पंचों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर गोदाम का ताला खुलवाया गया।

निरीक्षण के दौरान गोदाम में बिना लाइसेंस जैव उत्प्रेरक एवं कीटनाशकों के निर्माण के लिए कच्चा माल, तैयार उत्पाद, पैकिंग मशीनें तथा बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला। जांच में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम एवं नियमों के अनेक प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यवसाय, बिना मानक के उर्वरक निर्माण, निर्धारित अभिलेखों का संधारण नहीं करना, निरीक्षण में सहयोग नहीं करना तथा बिना स्रोत के कीटनाशकों का भंडारण जैसे गंभीर मामले सामने आए।

कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में जैव उत्प्रेरक, कीटनाशक, उर्वरक, रॉ मटेरियल, रसायनों से भरे ड्रम, पैकिंग एवं सीलिंग मशीनें तथा अन्य उपकरण जब्त किए गए। संपूर्ण सामग्री को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत जब्त कर गोदामों को सील किया गया है। कृषि विभाग ने संबंधित संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

मुख्यमंत्री की पहल :स्वस्थ माताएं, स्वस्थ बच्चे व कुपोषण मुक्त छग के लिए बनेगी समन्वित रणनीति

यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से सभी संबंधित विभाग मिलकर तैयार करेंगे प्रभावी कार्ययोजना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मंत्रालय महानदी भवन में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन तथा बच्चों के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में स्थायी सुधार के लिए सभी विभागों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वस्थ माताएं और स्वस्थ बच्चे ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिम जाति विकास विभाग सहित सभी संबंधित विभाग यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से एक समन्वित और परिणामोन्मुख काययोजना तैयार करें, जिससे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण में कमी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का प्रभाव तभी बढ़ेगा, जब विभिन्न विभाग साझा लक्ष्य और समन्वित कार्यप्रणाली के साथ काम करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी मल्टी–सेक्टोरल रणनीति तैयार करने को कहा, जिससे स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे और बच्चों के पोषण स्तर में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे का शॉल एवं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक 'नंदी' भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। वहीं सुश्री मैककैफ्रे ने भारत में यूनिसेफ के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट मुख्यमंत्री को भेंट किया। यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने मुख्यमंत्री का जय जोहार कहकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और सरल–सहज लोगों का प्रदेश है। उन्होंने बताया कि यूनिसेफ लंबे समय से राज्य सरकार के साथ मिलकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश के बच्चों का भविष्य अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ की प्रमुख सुश्री सीमा कुमार, अनिल गुलाटी तथा डॉ. बाल पारितोष दास उपस्थित थे।

विदाई कार्यक्रम समर्पण, सेवा और संस्कारों को भावभीनी विदाई , केंद्रीय विद्यालय में चार शिक्षकों का गरिमामय सेवानिवृत्ति समारोह सम्पन्न

"जीवन छुट्टी नहीं, नए अवसरों का उत्सव है" : डॉ. अजय आर्य

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

केंद्रीय विद्यालय में मंगलवार को चार समर्पित शिक्षकों के सम्मान में गरिमामय एवं भावपूर्ण सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने उनके दीघर्कालीन शैक्षिक योगदान को याद करते हुए भावभीनी विदाई दी। सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों में के. लक्ष्मण राव टीजीटी शारीरिक शिक्षा, वी. मनोज टीजीटी गणित, श्रीमती नीलम शर्मा प्राथमिक शिक्षिका और डॉ. ज्ञानशंकर श्रीवास टीजीटी शारीरिक शिक्षा शामिल हैं।

"संबंधों का अंत नहीं है सेवानिवृत्ति"

विद्यालय के प्राचार्य अशोक चंद्राकर ने कहा कि "सेवानिवृत्ति केवल शासकीय सेवा का समापन है, संबंधों का नहीं। आप सभी सदैव केंद्रीय विद्यालय परिवार का अभिन्न अंग रहेंगे।" उन्होंने सभी शिक्षकों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उनके योगदान की सराहना की। समारोह में भावपूर्ण गीतों, संस्मरणों और शुभकामना संदेशों ने वातावरण को भावविभोर कर दिया। शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा कर सेवानिवृत्त साथियों के व्यक्तित्व को नमन किया।

"नए अध्याय का शुभारंभ है सेवानिवृत्ति"

केंद्रीय विद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र गिरी ने कहा कि संगठन की पहचान शिक्षकों की निष्ठा और राष्ट्रनिर्माण के प्रति प्रतिबद्धता से बनी है। ऐसे शिक्षक संगठन की वास्तविक शक्ति हैं। संघ के महासचिव डॉ. अजय आर्य ने प्रेरक उद्बोधन में कहा, "मनुष्य को अपने मन का कार्य अवश्य करना चाहिए। जीवन छुट्टी नहीं है। सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि अनुभव, सेवा और सृजन के नए अध्याय का शुभारंभ है।" कार्यक्रम में संघ की ओर से अध्यक्ष शैलेंद्र गिरी और डॉ. अजय आर्य ने सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति–चिह्न भेंट कर दीर्घ, स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दीं।

संचालन और उपस्थिति

कार्यक्रम का संचालन रश्मि द्विवेदी टीजीटी संस्कृत, आदिल यजदानी टीजीटी अंग्रेजी और अनामिका कश्यप प्राथमिक शिक्षिका ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उपप्राचार्य मसकीले मैडम सहित एनडी साहू, बीआर गजपाल, सुशांत डे, शशांक श्रीवास्तव, सुनीता गावंडे, जीवेश साहू, प्रभा सेठ तथा विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक एवं कमर्चारी उपस्थित रहे।

2 करोड़ की ठगी, नवा रायपुर से पति–पत्नी गिरफ्तार

रायपुर। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले शातिर पति–पत्नी को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन और चेकबुक जब्त की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हेमदत्त केशरवानी ने 24 मई को थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी पहचान मारुति विहार कॉलोनी निवासी हरिशंकर गुप्ता से थी। हरिशंकर और उसकी पत्नी रेखा गुप्ता ने उसे शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने पर भारी मुनाफे और रकम दोगुनी होने का झांसा दिया। दंपति की बातों में आकर प्रार्थी समेत अन्य लोगों ने चेक और RTGS के माध्यम से कुल 2,04,97,502 आरोपियों के बैंक खातों में जमा करा दिए। शुरुआत में विश्वास जीतने और टालमटोल करने के लिए आरोपियों ने महज 39,99,400 वापस किए, लेकिन बाकी रुपये लौटाने से लगातार मना करते रहे और आखिर में पूरी राशि का गबन कर लिया। मामला दर्ज होने की भनक लगते ही दोनों आरोपी फरार हो गए और लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

–:: ईश्तहार ::–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय का रा.प्र.क्रं. ...अ-6/वर्ष 2025-26 में आवेदिका/आवेदक - सुनयना थानथराटे आ./ध.प. स्व. प्रवीण कुमार निवासी– वैशाली नगर भिलाई तह. दुर्ग व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम–खेदामारा प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. जेवरा सिरसा व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 87/17 रकबा 0.03 हे. है। जो भूमि स्वामी प्रवीण कुमार आ. चन्द्रिका प्रसाद के नाम पर दर्ज है। जिसमें भूमिस्वामी प्रवीण कुमार की मृत्यु दिनांक 13/04/2021 को फौत हो जाने के कारण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसानो का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि फौती नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 21/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/06/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

–:: ईश्तहार ::–

रा.प्र.क्र. 202607101000146– ब–121 वर्ष 2025–26

एदत् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक विनोद गोयल / ध.प. श्री विजय गोयल निवासी - न्यू खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग, द्वारा अपने पुत्र/पुत्री/स्वयं विनोद गोयल का जन्म/मृत्यु तह. व दिनांक 03/11/1983 को करूणा हॉस्पिटल भिलाई तह. व जिला दुर्ग में जन्म/ मृत्यु हो जाने के कारण जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अतः जिस किसी व्यक्ति एवं संस्था को इस संबंध में आपत्ति एवं दावा उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 30/07/2026 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कायर्वाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16/7/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया हैं।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

संपादकीय

तथ्य व तर्क नहीं होते इसलिए होता है हंगामा

संसद के कई सत्र हो गए हैं,हर बार उम्मीद की जाती है कि इस बार संसद सत्र सामान्य रहेगा,संसद में हर विषय पर चर्चा होगी और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सरकार हर सवाल का जवाब देगी। हर बार देश की जनता को विपक्ष ने निराश किया है। हर बार किसी एक मुद्दे या कुछ मुद्दों को उठाकर विपक्ष के नेता संसद हंगामा करने आते हैं और संसद को चलने नहीं देते हैं और संसद न चलने देने के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं। ऐसा क्यों होता है यह पीएम मोदी जानते हैं इसलिए वह संसद शुरू होने के पहले ही सीधे यह नहीं बताते हैं कि इस बार भी पिछली बार के समान ही विपक्ष संसद में हंगामा करेगा और संसद नहीं चलने देगा। वह यह बताते हैं कि विपक्ष संसद में हंगामा करता है, संसद चलने नहीं देता है, बहस नहीं करता है, सवाल नहीं पूछता है, जवाब नहीं सुनता है तो उसकी वजह है विपक्ष के पास न तर्क है न तथ्य है इसलिए तर्क व तथ्य न होने के कारण वह हंगामा करता है, संसद नहीं चलने देना चाहता है।

इस बार भी संसद सत्र के पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को हल्ला न करने की नसीहत देते हुए कहा है कि जब तथ्य व तर्क मजबूत होते हैं तो हंगामे के लिए कोई जगह नहीं बचती है। अगर तर्क मजबूत है,तथ्य ठोस है तो शांत चित्त से अपनी आवाज को बुलंद किया जा सकता है।तर्क व तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृध्द बनाया जा सकता है।हर आवाज व हर विचार को संसद में जगह मिल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में कई अनुभवी सासंद हैं, कई दलों के पास अनुभवी सांसद है,उनके अनुभव व उनके ज्ञान की संसद को जरूरत है।देश को भी जरूरत है,इसके लिए संसद का चलना,संसद में सार्थक चर्चा होना,मिलजुल कर देश को आगे ले जाने का संकल्प लेना जरूरी है। मोदी तो चाहते हैं कि संसद में बहस हो,अनुभवी सांसदों को सहयोग सरकार को मिले, लेकिन पार्टी राजनीति व पार्टी विरोध के चलते यह पिछले कई सत्रों से हो नहीं पाता है, पार्टी नेता जैसा चाहता है सासंदों को वैसा ही आचरण संसद में करना पड़ता है।इससे लोगों को भी लगता है कि हमने कैसे लोगों को संसद में चुनकर भेजा है।

मानसून सत्र के पहले दिन वही सब हुआ जो इससे पहले के सत्र में होता रहा है। लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने नीट पेपर लीक, राममंदिर चढ़ावा चोरी आदि मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी।इसके कारण प्रश्नकाल व शून्य काल नहीं हुआ। सदन की कार्यवाही छह बार स्थगित होने के बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई। संसद में विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की।कुछ सदस्यों ने आसन पार जाकर भी नारेबाजी की। लोकसभा के स्पीकर बार बार सदस्यों से कहते रहे कि संदन की गरिमा व परंपरा को बनाएं रखें नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। तर्कों के साथ चर्चा करें। विपक्षी सांसद हल्ला करते रहे। स्पीकर बिरला ने सदस्यों से यह भी कहा कि कई प्रदेशो मे बाढ़ की समस्या है,उस पर चर्चा कीजिए। लेकिन विपक्षी सदस्यों को हल्ला करना,हंगामा करना ही ज्यादा ठीक लगा और वह वही करते रहे।

देश की राजधानी दिल्ली व संसद में सोमवार जो कुछ दिल्ली की सड़क व संसद में देखने को मिला है वह लोकतंत्र के लिए शुभ तो नहीं माना जा सकता है। लोकतंत्र आपसी टकराव से मजबूत नहीं होता है, लोकतंत्र तो संवाद व सार्थक चर्चा से ही मजबूत होता है, एक दूसरे के सहयोग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। लोकतंत्र में टकराव किसी भी तरह से ठीक नहीं माना जा सकता है लेकिन चाहे सड़क हो या संसद हो वहां संवाद की जगह टकराव को चुना जा रहा है और इसी वजह छोटी छोटी बातों पर आए दिन संसद व सड़क पर सरकार व विपक्ष का टकराव देखने को मिल रहा है।देश का संविधान नागरिकों को सांसदों को शांति पूर्ण ढंग से अपनी बात रखने व सरकार का विरोध करने का अधिकार देता है। वह अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब भी ऐसा नहीं किया जाता है तो टकराव होता है और इससे सबको परेशानी होती है। सड़क पर अराजक आंदोलन या संसद में अराजक हंगामा हो दोनों से लोकतंत्र कमजोर होता है और संसद हो या सड़क हो सभी की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा कोई काम न करे कि लोकतंत्र कमजोर हो।

संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है तो सड़क लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सबसे ऊंचा मंच है। यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है कि संसद को सड़क न बनाया जाए और सड़क को संसद न समझा जाए।संसद व सड़क एक दूसरे के विकल्प नहीं है, वह एक दूसरे के पूरक हैं। सवाल सड़क पर उठाए जा सकते हैं लेकिन उस पर बहस सड़क पर नहीं हो सकती,सड़क पर बहस से कोई समाधान नहीं निकल सकता, उस पर बहस संसद में होगी तो कोई समाधान निकलेगा। सड़क पर उठने वाली आवाजें संसद तक पहुंचनी चाहिए। यह काम विपक्ष के सांसदों का है। विपक्ष के सांसदों को यह आवाज संसद में उठानी चाहिए, वह भी यदि सड़क के लोगों की तरह संसद में हंगामा करेंगे, संसद नहीं चलने देंगे तो न तो सड़क की आवाज संसद में उठ सकती है और समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। संसद देश की समस्याओं के समाधान का मंच है,यहां हंगामा होगा तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा।

योगी की जय कन्हैया व टेंशन में है अखिलेश भैया

अशोक भाटिया

योगी की जय कन्हैया व टेंशन में है अखिलेश भैया—यह महज उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपजा एक नया नारा या तात्कालिक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। असल में, यह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की पिच तैयार करने, राज्य की राजनीति को एक बड़े वैचारिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने और विपक्ष की सामाजिक घेराबंदी करने का एक बेहद दूरगामी और सुनियोजित खाका है। हाथरस की जनसभा से लेकर संभल, बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव को जिस प्रकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ब्रज संस्कृति के मुद्दे पर घेरा है, उसने सपा के रणनीतिकारों और थिंक-टैंक को एक बेहद गहरी टेंशन, कशमकश और राजनीतिक असमंजस में डाल दिया है।

यह नारा इस समय के पूरे सियासी घमासान के ऐतिहासिक संदर्भों, चुनावी गणित, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उभार, समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी अस्मितावादी दुविधा और भारतीय लोकतंत्र पर इसके पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का एक अत्यंत निष्पक्ष, गंभीर और विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए देश के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को समझना अनिवार्य है। भारतीय राजनीति में पिछले चार दशकों से अयोध्या, काशी और मथुरा की तिकड़ी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी विमर्श के केंद्र में रही है। जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे में स्वाभाविक रूप से अगला सबसे बड़ा पड़ाव मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि है।

यह ताजा राजनीतिक विवाद तब और अधिक गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुए राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी, वित्तीय अनियमितताओं और भूमि घोटालों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बयान दिया कि यदि भविष्य में प्रदेश में उनकी सरकार आती है, तो वे अयोध्या को एक आदर्श धार्मिक नगरी के रूप में और बेहतर ढंग से विकसित करेंगे ताकि वहां के स्थानीय निवासियों को असुविधा न हो।अखिलेश यादव के इसी आक्रामक दांव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद तीखा और रणनीतिक पलटवार किया। योगी ने जनसभाओं से सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा: अखिलेश जी, आप अयोध्या की चिंता छोड़िए, पहले अपने अतीत के फैसलों पर पश्चाताप करिए और एक बार प्रभु श्रीरामलला के चरणों में जाकर दर्शन कर आइए, जिससे आपको सद्बुद्धि आए। अगर आप वास्तव में खुद को धार्मिक और सनातनी साबित करना चाहते हैं, तो मथुरा-वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए खुलकर अपना स्टैंड साफ करिए। योगी आदित्यनाथ का यह तीखा बयान सपा को उसी की सॉफ्ट हिंदुत्व और यदुवंशी (यादव) पहचान की पिच पर घेरने की एक सोची-समझी राजनीतिक चाल है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस रणनीतिक घेराबंदी के पीछे कई ऐसे बिंदु हैं जो सीधे तौर पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को छूते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में लगातार जनता को यह याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के थानों, चौकियों और जेलों में पारंपरिक रूप से होने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के भव्य आयोजनों पर अघोषित या लिखित रूप से रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कांवड़ यात्राओं पर लगे पूर्ववर्ती प्रतिबंधों और लाठीचार्ज का भी जिक्र किया। इसके जरिए वे बहुसंख्यक हिंदू समाज के मन में यह संदेश गहरा करना चाहते हैं कि सपा का मूल चरित्र हमेशा से तुष्टिकरण से प्रेरित रहा है और सत्ता में आते ही वे बहुसंख्यक धार्मिक आस्थाओं को दबाने का प्रयास करते हैं।

भाजपा ने विकास के आर्थिक मॉडल को धार्मिक आस्था और अस्मिता से जोड़कर एक नया नैरेटिव तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने मंचों से कहते हैं कि 2017 से पहले जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने और विशेष त्योहारों के बिजली प्रबंधन में खर्च होता था, जबकि वतर्मान भाजपा सरकार उसी पैसे को अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और चित्रकूट के सौंदर्यीकरण तथा श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च कर रही है। यह सीधा तुलनात्मक विमर्श आम जनता के बीच गहरी छाप छोड़ता है।

ब्रज क्षेत्र और देश भर के प्रमुख संत समाज, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी शामिल है, ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आगामी 9 अगस्त 2026 को सांकेतिक रूप से कार सेवा करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। संतों ने सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव से सीधे तीखे सवाल किए हैं। संतों का कहना है कि यदि अखिलेश खुद को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज (यदुवंशी) मानते हैं, तो उन्हें इस पवित्र अभियान का खुलकर समर्थन करना चाहिए और कार सेवा के लिए पहला पत्थर उठाने के लिए खुद आगे आना चाहिए।

दरअसल अखिलेश यादव इस समय एक ऐसी त्रिशंकु स्थिति में फंस गए हैं जहां उनका हर एक कदम एक नया राजनीतिक जोखिम लेकर आ रहा है। इस टेंशन के तीन मुख्य पहलू हैं: 1: एम-वाई (M-Y) समीकरण के बिखरने का सीधा खतरा -समाजवादी पार्टी की मुख्य ताकत और चुनावी आधार पारंपरिक रूप से मुस्लिम (M) और यादव (Y) मतदाताओं के मजबूत और अटूट गठजोड़ पर टिका रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का मुद्दा उठाकर इसी गठजोड़ की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है:यदि अखिलेश मथुरा आंदोलन का समर्थन करते हैं तो उनका सबसे वफादार और एकजुट मुस्लिम वोटबैंक उनसे पूरी तरह से नाराज और ठगा हुआ महसूस कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय शाही ईदगाह मस्जिद के कानूनी और धार्मिक वजूद को बचाने के पक्ष में है।

उन्हें लगेगा कि सपा भी भाजपा के बहुसंख्यकवाद के आगे नतमस्तक हो गई है।यदि अखिलेश मथुरा आंदोलन का विरोध करते हैं: तो भाजपा और संत समाज उन्हें तुरंत सनातन विरोधी और मुस्लिम तुष्टिकरण का सबसे बड़ा पैरोकार घोषित कर देंगे। इससे यादव समुदाय और अन्य पिछड़ी जातियों का वह बड़ा हिस्सा, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर अत्यधिक भावुक और सजग है, सपा से छिटक कर भाजपा के पाले में जा सकता है।अखिलेश यादव अक्सर रैलियों में और भगवान कृष्ण की मूतिर्यां स्थापित करवाकर यह गर्व से कहते आए हैं कि भगवान कृष्ण मेरे भी सपने में आते हैं और हम उनके सच्चे वंशज हैं। लेकिन जब बात कानूनी विवादों, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे और मंदिर निर्माण के लिए सड़क पर उतरने की आती है, तो उन्हें अपनी पार्टी की वाम-प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखना होता है। यह वैचारिक अंतर्विरोध उनकी राजनीतिक शैली को कमजोर, रक्षात्मक और अस्पष्ट दिखाता है।

पहलू 3: राजनीतिक पिच पर भाजपा की रणनीतिक बढ़त -लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, कानून-व्यवस्था, और सांडों की समस्या जैसे बुनियादी धरातलीय मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रहे थे और उन्हें इसमें सफलता भी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि और कार सेवा का मुद्दा विमर्श के केंद्र में आया, पूरी राजनीतिक बहस का रुख एक बार फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर केंद्रित हो गया। भाजपा हमेशा से इस धार्मिक पिच पर खेलने में माहिर रही है, जिससे विपक्ष द्वारा उठाए गए बुनियादी और आर्थिक मुद्दे नेपथ्य में चले जाते हैं।

इस चौतरफा वैचारिक हमले और तनाव के बीच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हथियार डालकर नहीं बैठी है। वे भाजपा के इस भारी-भरकम धार्मिक राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी एक अलग और मूक रणनीति पर काम कर रहे हैं:असली बनाम नकली सनातन की बहस: अखिलेश यादव और उनके प्रखर प्रवक्ता टीवी चैनलों और रैलियों में यह तर्क दे रहे हैं कि वे भी सच्चे सनातनी हैं और भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन वे धर्म का उपयोग नफरत फैलाने, समाज को बांटने या वोट बटोरने के लिए नहीं करते। वे अक्सर भाजपा पर धर्म के व्यवसायीकरण और धार्मिक स्थलों पर स्थानीय दुकानदारों व पंडा-पुजारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं।

इस समय सपा का पूरा प्रयास यह है कि वे खुद को भाजपा द्वारा बुने गए इस धार्मिक विवाद के जाल में पूरी तरह से फंसने न दें। वे लगातार युवाओं की बेकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक, किसानों की फसलों के दाम, और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान उनकी बुनियादी और दैनिक जरूरतों की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय की ढाल और विधिक प्रक्रिया का सहारा: मथुरा और काशी के संवेदनशील मुद्दों पर सपा का आधिकारिक रुख हमेशा यह रहता है कि यह मामला चूंकि देश की माननीय अदालतों (हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) के विचाराधीन है, इसलिए सभी पक्षों को कानून और अदालती फैसले का सम्मान करना चाहिए। इसके जरिए वे किसी भी समुदाय को नाराज किए बिना सीधे विरोध या समर्थन करने की स्थिति से साफ बच निकलते हैं।

योगी की जय कन्हैया व टेंशन में है अखिलेश भैया का यह पूरा राजनीतिक प्रकरण यह साफ तौर पर दर्शाता है कि 21वीं सदी के भारत और विशेषकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में, राजनीति केवल आर्थिक पैमानों, बुनियादी विकास के दावों या पुराने जातिगत गठबंधनों के सहारे नहीं जीती जा सकती। यहाँ सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव मतदाताओं के व्यवहार और उनकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली और निर्णायक कारक बन चुके हैं।

एक जिला-एक उत्पाद : विष्णुभोग चावल की महक जिले की बनी पहचान

नई दृष्टिबिंदु / गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

छत्तीसगढ़ का 25वां नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अब विशिष्ट कृषि उत्पाद सुगंधित विष्णुभोग चावल के कारण भी नई पहचान बना रहा है। भारत सरकार की एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत विष्णुभोग चावल को जिले का प्रमुख उत्पाद चुना गया है। मनमोहक सुगंध, उत्कृष्ट स्वाद और जैविक खेती की परंपरा के कारण यह चावल आज जिले की पहचान बन चुकी है। विष्णुभोग चावल की खुशबू अब केवल खेतों तक सीमित नहीं होकर जिला, प्रदेश और देश के अन्य राज्यों तक फेल रहा है। पारंपरिक तरीके से उगाई जाने वाली यह धान की किस्म गुणवत्ता और पौष्टिकता के लिए विशेष रूप से जानी जाती है।

जिले के पेंड्रा क्षेत्र में लगभग 1,500 किसान मिलकर करीब 600 एकड़ भूमि पर विष्णुभोग धान की खेती कर रहे हैं। किसानों के सामूहिक प्रयास और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदमों ने इस उत्पाद को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ जिले की कृषि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। केवल खेती तक ही नहीं, बल्कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मलनिया महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पेंड्रा द्वारा किसानों से विष्णुभोग धान खरीदी जाती है। इसके बाद धान को मिनी राइस मिल में प्रसंस्करण कर आकर्षक पैकेजिंग के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य से समूह की 15 महिला सदस्यों को स्थायी रोजगार मिला है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर लखपति दीदी की ओर अग्रसर है।

समूह की महिलाओं ने अब तक लगभग 2 टन विष्णुभोग चावल की सफलता पूर्वक बिक्री कर चुकी हैं, इससे उन्हें करीब 1 लाख रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। इसकी गुणवत्ता और सुगंध के कारण अब इसकी मांग जिले से बाहर अन्य जिलों और विभिन्न राज्यों से भी लगातार बढ़ रही है। यह स्थानीय उत्पाद अब व्यापक बाजार में अपनी अलग पहचान स्थापित कर रहा है। एक जिला-एक उत्पाद योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि स्थानीय संसाधनों, किसानों की मेहनत और महिला शक्ति को सही दिशा मिले, तो कोई भी पारंपरिक उत्पाद राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। विष्णुभोग चावल आज जीपीएम जिले के किसानों की समृद्धि, महिलाओं के स्वावलंबन और स्थानीय उद्यमिता का सशक्त प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में यदि विष्णुभोग चावल के उत्पादन, ब्रांडिंग और विपणन को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है, तो यह न केवल जीपीएम जिले की आर्थिक प्रगति का आधार बनेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि विरासत को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा।

कविता का कोना

बड़ा गुमान है

कल कि खबर नहीं है बन्दे, फिर
भी बड़ा गुमान है,
माटी कि यह देह मिली है, करते
अति अभिमान हैं।
चार दिनों का जीवन पाया, कभी
बुलावा आ जायेगा,
चार दिनों की यहाँ चाँदनी, कभी
अँधेरा छा जायेगा।
थोड़ा सा धन पा जाते हो, रावण
सा इतराते हो,
नहीं किसी की सुनते भाई,
मनमानी करते जाते हो।
जितना माल कमाया तुमने, कौड़ी
काम नहीं आयेगी,
जितने महल बनाये तुमने अंत
काम माटी आयेगी।
बड़ी शान से चलते भू पर,
अहंकार में जीते हो,
अपमानित करते लोगों को, उनका
चैन लूटते हो।
क्यों गुमान करते
दौलत पर, धेला
संग ना जायेगा,
जितना दान पुण्य
करते हो, वही साथ
में जायेगा।
कुछ भी संग न
जाने वाला, पड़ा यही रह जायेगा,
तन को रोज सजाते हो तुम, वो भी
तो जल जायेगा।
कल कि खबर नहीं है भाई, बनते
बड़े मकान हैं,
अहंकार में डूबा मानव, कर देते
अपमान है।

छत्तीसगढ़ रत्न
डॉ. शिरोमणि माथुर

कविता

जिंदगी अभी बाकी है......

कुछ लम्हें जिंदगी के बचपन में
कट गए
स्कूल की दहलीज पर घर की यादें
छूट गई
बीत गया वह खुशनुमा सुनहरा सा
पल
जब कॉलेज की कक्षा में पढ़ना
सीख गया

तुम बैठी इंतजार करती रहीं, हर
सांझ लौटने का
वह सांझ मुझे कभी न मिली
माँ! तुम कितनी भोली थीं
भूल गई अपना जहान
सर्वस्व लुटा दिया जीवन भर
परिवार के नाम
बच्चों को जीवन का ढंग सिखाते-
सिखाते
खुद भूल गई जिंदगी का रंग
ओ माँ! तूने दुनिया रची
भूख-प्यास और त्याग-समर्पण से
मुझे पढ़ना-लिखना सिखाकर
चुप-चाप चली गई
वह बचपन कितना अच्छा था
जब सुबह-शाम मेरे लौटने का
इंतजार करती थीं
अब तुम्हें ढूंढता हूँ माँ
कैसे कहूँ? तुम चली गई जीवन से
तुम आज भी मेरे हृदय में धड़कती
हो
तुम चली गई, कुछ बरस और न
ठहरीं?
मेरे संघर्ष में साथ रहतीं मेरे साथ
जिंदगी अभी बाकी है...
तुम्हारे बगैर

(प्रथम पुण्यतिथि पर माँ श्रीमती नीरा बाई लहरे जी को समर्पित रचना, 30 जून 1961_ 23 जुलाई 2025
लक्ष्मीनारायण लहरे "साहिल"
साहित्यकार, पत्रकार, सारंगढ़

चंद्रशेखर आजाद — भारत का वह पुत्र, जिसने सिर झुकना सीखा ही नहीं

कृति आरके जैन

कभी-कभी इतिहास राजाओं के मुकुट से नहीं, एक साधारण युवक की भींची हुई मुट्ठी से बदलता है। साम्राज्य हमेशा तोपों से नहीं टूटते, वे अडिग संकल्प के सामने भी ढह जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा ही एक संकल्प जन्मा था— चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने केवल अंग्रेजी सत्ता को चुनौती नहीं दी, बल्कि भारतीयों के मन में जड़ जमा चुके भय और मानसिक गुलामी पर भी प्रहार किया। वे जानते थे कि जिस दिन भारतीय का भय टूट जाएगा, उसी दिन साम्राज्यवाद की नींव भी हिल जाएगी। इसलिए उनका संघर्ष केवल हथियारों का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के जागरण का था।

23 जुलाई 1906 को तत्कालीन अलिराजपुर रियासत (वर्तमान मध्यप्रदेश) के भाबरा गांव में जन्मा वह बालक किसी राजमहल का वारिस नहीं था। न उसके पास धन था, न सत्ता, न सेना; पर उसके भीतर ऐसा स्वाभिमान था, जो किसी भी साम्राज्य से विशाल था। इतिहास साक्षी है कि जब किसी राष्ट्र की मिट्टी ऐसे सपूतों को जन्म देती है, तब गुलामी की उम्र सिमटने लगती है। जलियांवाला बाग का रक्तपात केवल निदोषों की हत्या नहीं था, वह एक पूरी पीढ़ी के हृदय में प्रतिकार की ज्वाला बनकर धधक उठा। उसी ज्वाला ने चंद्रशेखर के मन में ऐसा अटूट संकल्प जगाया, जिसे कोई शक्ति डिगा न सकी। उन्होंने समझ लिया था कि अन्याय अपने आप समाप्त नहीं होता; उसे साहस, त्याग और मृत्यु से भी बड़े संकल्प से परास्त करना पड़ता है।

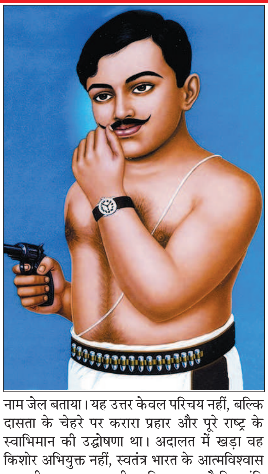

किशोर अवस्था में 1921 में जब उन्हें अंग्रेजी अदालत में पेश किया गया और नाम पूछा गया, तो उन्होंने कहा — आजाद। पिता का नाम स्वतंत्रता और गांव का नाम जेल बताया। यह उत्तर केवल परिचय नहीं, बल्कि दासता के चेहरे पर करारा प्रहार और पूरे राष्ट्र के स्वाभिमान की उद्घोषणा था। अदालत में खड़ा वह किशोर अभियुक्त नहीं, स्वतंत्र भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था। उनका जीवन सिद्ध करता है कि क्रांति केवल हथियार उठाने से नहीं, भय को पराजित करने से जन्म लेती है। जिस मनुष्य के भीतर भय समाप्त हो जाए, उसे संसार की कोई शक्ति झुका नहीं सकती। यही कारण था कि अंग्रेजी शासन उनके शरीर को तो घेर सका, पर उनके अदम्य आत्मबल को कभी बंदी नहीं बना सका।

चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को केवल संगठन नहीं, अटूट विश्वास दिया। उन्होंने सिखाया कि राष्ट्र का निर्माण नारों से नहीं, त्याग और समर्पण से होता है। उन्होंने अपने लिए कभी घर नहीं बसाया, क्योंकि पूरा भारत ही उनका घर था। उन्होंने अपने भविष्य से अधिक राष्ट्र के भविष्य को चुना। उनका सबसे बड़ा शस्त्र उनका चरित्र था। वे जानते थे कि अनुशासन के बिना संघर्ष सफल नहीं होता, नैतिकता के बिना क्रांति टिकती नहीं और संगठन के बिना बलिदान इतिहास नहीं रचता। इसलिए उनका जीवन अनुशासन, त्याग और राष्ट्रसमर्पण का पर्याय बन गया। उनका प्रत्येक क्षण राष्ट्र की अमानत था।

आज जब हम स्वतंत्र भारत में साँस लेते हैं, तब यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए—क्या हम वास्तव में उतने ही स्वतंत्र हैं, जितना हमारे पूर्वज हमें बनाना चाहते थे? यदि समाज भ्रष्टाचार से समझौता कर ले, यदि युवा सुविधा को संघर्ष से बड़ा मानने लगे, यदि राष्ट्रहित से पहले स्वार्थ खड़ा हो जाए, तो क्या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त है? चंद्रशेखर आजाद आज भी इसी प्रश्न का उत्तर बनकर हमारे सामने खड़े हैं। उनका जीवन कहता है कि पराधीनता केवल विदेशी शासन नहीं होती। जब चरित्र बिकने लगे, जब सत्य डरने लगे, जब अन्याय देखकर भी समाज मौन रहे, तब समझ लेना चाहिए कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ अभी अधूरा है।

आज के युवाओं को चंद्रशेखर आजाद से हथियार नहीं, साहस; विद्रोह नहीं, अनुशासन; और अन्याय के सामने अडिग रहने का चरित्र सीखना चाहिए। राष्ट्र केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से महान बनता है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब आजाद पार्क) में चारों ओर से घिर जाने पर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। यह केवल एक क्रांतिकारी का अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि उनकी प्रतिज्ञा का अंतिम निर्वाह था। उन्होंने प्राण त्याग दिए, पर विदेशी सत्ता के सामने कभी नहीं झुके। उनका शरीर गिरा, पर उनका स्वाभिमान और संकल्प अमर हो गया। चंद्रशेखर आजाद आज भी भारतीय आत्मसम्मान, अदम्य साहस और स्वतंत्रता-चेतना के शाश्वत प्रतीक हैं।

आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम केवल उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाएँ। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर बैठे भय, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, कायरता और उदासीनता के विरुद्ध क्रांति करें। यदि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और राष्ट्रधर्म को सर्वोच्च स्थान दे दे, तो यही चंद्रशेखर आजाद के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 23 जुलाई हर वर्ष कैलेंडर पर आती है, लेकिन उसका वास्तविक महत्व तभी है जब वह हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगा सके। यह दिन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि स्वाभिमानी नागरिकों से जीवित रहता है। स्वतंत्रता केवल संविधान में नहीं बसती, वह प्रत्येक भारतीय के चरित्र में दिखाई देनी चाहिए।

चंद्रशेखर आजाद आज इतिहास की पुस्तक का एक अध्याय भर नहीं हैं। वे उस प्रश्न का उत्तर हैं, जो हर पीढ़ी से पूछा जाएगा—जब अन्याय सामने था, तब तुमने क्या किया? वे उस साहस का नाम हैं, जो परिस्थितियों का दास नहीं बनता। वे उस स्वाभिमान का नाम हैं, जो मृत्यु स्वीकार कर सकता है, पर पराधीनता नहीं। जब तक भारत की मिट्टी में आत्मसम्मान जीवित रहेगा, जब तक कोई युवा अन्याय के सामने सिर झुकाने से इंकार करेगा, जब तक राष्ट्र के लिए त्याग करने वाले लोग जन्म लेते रहेंगे—तब तक चंद्रशेखर आजाद जीवित रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग जीवन जीकर नहीं, अपने विचारों से अमर होते हैं; और आजाद उन्हीं अमर विचारों का सबसे तेजस्वी नाम हैं।

खास खबर

दक्षिण अफ्रीका में डबल गोल्ड जीतने वाले जयदीप साहू का खेल मंत्री अरुण साव ने किया सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

डोप-फ्री खेल संस्कृति को बताया सफलता का आधार

छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को रायपुर स्थित निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में दक्षिण अफ्रीका में दो स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टर जयदीप साहू का सम्मान किया। इस अवसर पर उनके कोच एवं पिता कृष्णा साहू का भी विशेष सम्मान किया गया। कृष्णा साहू पूर्व अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय निर्णायक हैं और विक्रम, गुंडाधुर एवं वीर हनुमान खेल पुरस्कार से सम्मानित हैं।

डोप-फ्री तैयारी से मिली सफलता : सम्मान समारोह में कृष्णा साहू ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) की भूमिका प्रतियोगिता में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। प्रतियोगिता के दौरान कई खिलाड़ियों के यूरिन सैंपल लिए गए। हअऊ्र के नियमों के अनुसार डोप-मुक्त वातावरण में समान अवसर देने के लिए प्रतियोगिता, अभ्यास या आवश्यकता पड़ने पर निवास स्थान पर भी सैंपल लिया जा सकता है। खेल मंत्री अरुण साव ने जयदीप से दो स्वर्ण जीतने के अनुभव पूछे। जयदीप ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से पिता के मार्गदर्शन में पूर्णतः डोप-फ्री रहकर प्राकृतिक आहार और कठोर अभ्यास से तैयारी कर रहे हैं। इसी अनुशासन, छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग संघ के सहयोग और साथी खिलाड़ियों के समर्थन से उन्हें दो स्वर्ण पदक मिले। जयदीप ने परिवार, संघ के पदाधिकारियों और खेल मंत्री का आभार जताते हुए शासकीय नौकरी प्रदान करने संबंधी साहू समाज का अनुरोध पत्र भी सौंपा।

तीन खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान : उल्लेखनीय है कि जयदीप साहू, अमन शुक्ला और प्रियंक मिश्रा ने दक्षिण अफ्रीका के पॉचेफस्ट्रूम शहर में 4 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित एशियन, अफ्रीकन एवं पैसिफिक अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतकर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग संघ के कायर्कारी अध्यक्ष तुलसी सोनी, डीएसपी एवं सहायक संचालक रुस्तम सारंग, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं ओलंपियन रेणुका यादव, कुमार जैन और राजेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे और जयदीप व कृष्णा साहू को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को 17 अगस्त की बोल बम कांवर यात्रा का निमंत्रण

'एक मुट्ठी दान भगवान शंकर के नाम' अभियान से 40 हजार भक्तों के लिए बनेगा महाप्रसाद

नई दृष्टिबिंदु / पाटन

बोल बम कांवर यात्रा समिति पाटन के संयोजक और भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से सौजन्य भेंट कर 17 अगस्त को आयोजित होने वाली विशाल बोल बम कांवर यात्रा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

इस अवसर पर वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को यात्रा की रूपरेखा, तैयारियों और आयोजन के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी पाटन से टोलाघाट तक हजारों शिवभक्तों की सहभागिता से भव्य कांवर यात्रा निकाली जाएगी।

सनातन संस्कृति और जनआस्था का उत्सव

जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि बोल बम कांवर यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, सेवा, अनुशासन और जनआस्था का विराट उत्सव है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु "बोल बम" के जयघोष के साथ पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।

आयोजन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए चिकित्सा सहायता, पेयजल, भोजन, विश्राम, सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आमंत्रण स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जितेन्द्र वर्मा और समिति के सदस्यों को आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

एक मुट्ठी दान से बनेगा महाप्रसाद

समिति ने बताया कि कांवर यात्रा के दिन "एक मुट्ठी दान, भगवान शंकर के नाम" अभियान के तहत श्रद्धालुओं से प्राप्त अन्नदान से महाप्रसाद तैयार किया जाएगा। यात्रा में शामिल होने वाले हजारों श्रद्धालु टोलाघाट पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। इस वर्ष भी 40 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है।

उपसरपंच की जीत बनी सजा की वजह

ग्राम विकास समिति ने सरपंच और 3 महिला पंचों पर लगाया 94 हजार का दंड

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उसरीबोड़ में 14 जुलाई को उपसरपंच के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद गांव में नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम विकास समिति ने अविश्वास प्रस्ताव में उपसरपंच के पक्ष में मतदान करने का आरोप लगाते हुए सरपंच और तीन महिला पंचों पर आर्थिक दंड लगाया है।

क्या है पूरा मामला

सूत्रों के अनुसार ग्राम विकास समिति ने उपसरपंच देवराज निषाद पर विभिन्न आरोप लगाकर उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था। मतदान में प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और देवराज निषाद अपने पद पर बने रहे।

उपसरपंच की जीत के बाद समिति ने बैठक कर निर्णय लिया कि जिन पंचों और सरपंच के कारण प्रस्ताव गिरा, उन पर दंड लगाया जाए। इसके तहत तीन महिला पंचों पर 21-21 हजार रुपये और सरपंच पर 31 हजार रुपये का दंड निर्धारित किया गया है। कुल 94 हजार रुपये का दंड लगाया गया है।

गांव में चर्चा तेज

इस निर्णय के बाद उसरीबोड़ में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान के आधार पर दंड लगाना उचित नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि समिति ने अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।

कोई आधिकारिक जानकारी व प्रशासन ने नहीं की पुष्टि

अब तक इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी या पुष्टि सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि पंचों या सरपंच द्वारा कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज की जाती है तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के बाद दंड की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की राजनीति और ग्रामीण माहौल गरमा गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दंडित पंच और सरपंच इस फैसले के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं।

मुद्दे की बात

डॉ.सोनाली चक्रवर्ती के साथ

ग्लोबल वार्मिंग से बड़ी समस्या है जनसंख्या

न्यूज दिखा- देहरादून-ऋषिकेश हाईवे के सात मोड़ क्षेत्र में लगभग 3,000 से ज्यादा पेड़ केवल सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जाने थे। इसकी वजह बढ़ता पर्यटन और और बढ़ती जनसंख्या के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग।

मेरी स्लम क्लास के एक बच्ची ने बताया- " हम लोग 6 बहने हैं पापा को बेटा चाहिए था। अब पापा नहीं रहे इसलिए घर में सभी लोग काम करते हैं ।बड़ी बहनें खुद काम करके छोटी बहनों को पढ़ा रही है। इन दोनों घटनाओं में कोई साम्यता नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में घूम रहा है कि हम इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करते जो कि सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है वह है जनसंख्या विस्फोट। बेटे की आशा में 6 से 8 लड़कियों का किसी घर में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई हमारे देश में लेकिन उनको सही शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और भविष्य दे सकते में अक्षम परिवार ही अधिकतर ऐसे कदम उठाते हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 1,02,87,37,436 (लगभग 1.02 अरब या 102.8 करोड़) थी। इसमें 53,22,23,090 पुरुष और 49,65,14,346 महिलाएँ शामिल थीं। यह पहली बार था जब भारत की जनसंख्या ने एक अरब का आंकड़ा पार किया था। जुलाई 2026 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1.47 अरब (147 करोड़) से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 17.8% हिस्सा अपने पास रखता है। हर साल भारत की जनसंख्या में लगभग 1.2 करोड़ (12 मिलियन) से 1.3 करोड़ लोगों की वृद्धि हो रही है।

जनसंख्या बढ़ने के कारण पेड़ों की कटाई और वनों के विनाश के मुख्य कारण हैं शहरीकरण और आवासीय विस्तार। बढ़ती आबादी को बसाने के लिए नए घर, टाउनशिप और शहरों का विस्तार हो रहा है, जिसके लिए जंगलों और खेतों को साफ किया जा रहा है ।भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्रों में बड़े पेड़ों को भी हटा दिया गया है ।सड़कों, बांधों, उद्योगों और खनन परियोजनाओं के माध्यम से तेजी से औद्योगीकरण हो रहा है, जो पेड़ों की कटाई का एक बहुत बड़ा कारण है।

एक विश्लेषण के अनुसार, जुलाई 2023 से मई 2026 के बीच केवल वन भूमि पर ही 2.8 मिलियन से अधिक पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई या दर्ज किया गया। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मुख्य कारण नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और बुनियादी ढाँचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का विकास है। पर्यटकों और चारधाम यात्रा के बढ़ते दबाव को देखते हुए सड़कों को 4-लेन और 6-लेन में बदला जा रहा है।

पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा के समय को कम करने के नाम पर अक्सर राज्य में बड़े वन क्षेत्रों को साफ किया जाता है। इस कटाई के खिलाफ स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से चिपककर विरोध प्रदर्शन किया है ।भारी विरोध को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल इन पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है और सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने की बात कही है ।राज्य निर्माण के बाद से अब तक विकास कार्यों के लिए 46,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ में पेड़ों की कटाई मुख्य रूप से कोयला खनन और अन्य औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए की जा रही है ।इसका सबसे प्रमुख और विवादित केंद्र राज्य का हसदेव अरण्य क्षेत्र है, जिसे 'मध्य भारत का फेफड़ा' भी कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की कटाई के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं विद्युत उत्पादन के लिए कोयला। हसदेव-अरण्य क्षेत्र में कई कोयला खदानें आवंटित की गई हैं। इन खदानों से निकाला गया कोयला मुख्य रूप से अन्य राज्यों (जैसे राजस्थान) में बिजली संयंत्रों को भेजा जाता है।

इन खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्यावरण और वन मंजूरी दी गई है, जिसके तहत लाखों पेड़ों को काटने की योजना है। इस कटाई का स्थानीय आदिवासी समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे न केवल जैव विविधता और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, बल्कि आदिवासियों की आजीविका भी खतरे में पड़ रही है।

सोचने वाली बात यह है कि इस सब की वजह है बढ़ती जनसंख्या और नागरिकों के लिए सुविधाओं की आवश्यकता। कई पर्यावरणविदों और अथर्शास्त्रियों का मानना है कि भारत के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए देश की आदर्श जनसंख्या 50 से 70 करोड़ के बीच होनी चाहिए, ताकि पानी, कृषि योग्य भूमि और जंगलों पर दबाव कम हो और सभी को उच्च गुणवत्ता वाला जीवन मिल सके।

इसका साफ-साफ अर्थ है कि देश में जनसंख्या लगभग दुगनी है। पेड़ों की कटाई से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक, लड़कियों को शिक्षा व रोजगार के अवसर न दे पाने से लेकर पीने के पानी और ऑक्सीजन की कमी तक हर चीज के लिए जिम्मेदार बढ़ती जनसंख्या है जिस पर कुछ कड़े कदम और कानून बनने का आ गया है।

अगर आपको भी लगती है कि यह बात सही है तो अपने विचार जरूर बतायें

HMGM जन सेवा समिति के नि :शुल्क स्वास्थ्य शिविर का चतुर्थ दिवस संपन्न

भाजपा नेताओं ने आयोजन की सराहना की, जनसेवा को बताया प्रेरणादायी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में HMGM जन सेवा समिति (मोदी ग्रुप) द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का चतुर्थ दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया।

इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेश बृजपुरिया, झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ की शारदा गुप्ता, "मन की बात" के प्रदेश सह-प्रहरी नितेश मिश्रा, आर्थिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यसमिति के अशोक कुमार द्विवेदी, परमानंद देव पांडेय एवं रतन पेठे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सभी अतिथियों ने स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन किया और आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनसेवा का यह प्रयास समाजहित में अत्यंत प्रेरणादायी है। समिति द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए नेताओं ने भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी आयोजनों के निरंतर संचालन के लिए शुभकामनाएं दीं।

HMGM जन सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।

खेत में करंट लगने से महिला की मौत

बेमेतरा। जिले के थान खम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुवारा में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में कृषि कार्य करने गई एक महिला की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में नमी के कारण महिला का पैर फिसल गया और वह जमीन के पास झूल रहे खुले सर्विस वायर के संपर्क में आ गई, जिससे उसे तेज करंट लगा। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतका की पहचान मनीषा यादव उम्र 33 वर्ष, पति सीताराम यादव, निवासी ग्राम गुवारा के रूप में हुई है। मनीषा अपने परिवार के भरण-पोषण में सहयोग के लिए रोजाना की तरह बुधवार सुबह खेत में काम करने गई थी। इसी दौरान अचानक हुए हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

गुरुवार तड़के सेंट्रल एवेन्यू भिलाई पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, दो की मौत

टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को दी सूचना

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बीएसपी टाउनशिप के सेंट्रल एवेन्यू में गुरुवार तड़के सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हादसा तड़के 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कार सवार दोनों युवक काफी तेज रफ्तार में थे और सेक्टर-10 गुंडिचा मंडप के पास सड़क किनारे पेड़ से टकरा गए। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही भिलाई नगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को मरच्यूरी पहुंचाया। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक सेक्टर-6 सड़क 35 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवकों के नाम दीपक गुप्ता और कौशिक दास बताया जा रहा है। सुबह-सुबह 4 बजे सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही कार क्रमांक CG 07 MB 5986 पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार में सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नेहरू नगर से वापस लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और हादसा हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। दोनों युवकों के शवों को मरच्यूरी रवाना किया गया। वहीं हादसे की सूचना युवकों के परिजनों को दे दी गई है। आरटीओ के रिकार्ड के अनुसार कार क्रमांक CG 07 MB 5986 सड़क 46 सेक्टर -6 निवासी एस गौरी प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड है। शुरुआती जांच में कार के भीतर शराब की बोतल व अन्य सामान मिला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ड्राइविंग सीट पर कौन था और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार हादसे की एक संभावित वजह मानी जा रही है। फिलहाल भिलाई नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

नई व्यवस्था | डीजीपी अरुणदेव गौतम की रिपोर्ट के बाद सरकार ने लिया फैसला

एक जिले में दो पुलिस व्यवस्थाएं बनीं परेशानी, पूरे जिले में कमिश्नरी लागू करने की तैयारी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राजधानी रायपुर में लागू दोहरी पुलिस व्यवस्था अब सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। पुलिस कमिश्नरी और रायपुर ग्रामीण की अलग-अलग व्यवस्था लागू होने के 179 दिन के भीतर ही इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं।

डीजीपी अरुणदेव गौतम ने शासन को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि एक ही जिले में दो तरह की पुलिसिंग से कानून-व्यवस्था, वीआईपी ड्यूटी और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट में पूरे जिले में एकीकृत कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई है।

कमिश्नरी में अपराध घटे, देहात में बढ़े

पुलिस मुख्यालय की 100 दिन की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कमिश्नरी क्षेत्र में अपराधों में कमी और पुलिस की कार्रवाई में इजाफा हुआ है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में पुलिसिंग कमजोर हुई है और अपराध बढ़े हैं।

डीजीपी द्वारा गठित एडीजी स्तर की उच्च स्तरीय समिति ने भी माना है कि पर्याप्त पुलिस बल और संसाधनों के बिना दोहरी व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। इससे पुलिसिंग का स्तर गिरेगा और सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

तबादले और वीआईपी ड्यूटी में उलझन

रिपोर्ट में बताया गया कि एक ही जिले में होने के बावजूद सिपाही और हवलदार के तबादलों के लिए फाइल डीजीपी स्तर तक भेजनी पड़ रही है। शासन की अनुमति के बिना नवा रायपुर का स्टाफ शहर में पदस्थ नहीं हो सकता।

एयरपोर्ट, विधानसभा और मंत्रालय जैसे संवेदनशील वीवीआईपी क्षेत्र ग्रामीण पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हैं, जबकि ग्रामीण एसपी और आईजी कार्यालय कमिश्नरी क्षेत्र में स्थित हैं। कई वार्ड और पंचायतें भी अधिसूचना के विपरीत बंटी हुई हैं। वरिष्ठ विधायक भोलाराम साहू ने भी दोहरी व्यवस्था के कारण विधानसभा में गलत जवाब प्रस्तुत होने का मामला उठाया है।

50 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त खर्च

रायपुर ग्रामीण के लिए अलग पुलिस जिला बनाए रखने पर सरकार को 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने होंगे। इसके लिए अलग एसपी कार्यालय, पुलिस लाइन, आवास, महिला थाना, अजाक थाना, क्राइम ब्रांच और ट्रैफिक का नया ढांचा तैयार करना पड़ेगा। अभी ग्रामीण एसपी संभागीय आयुक्त कार्यालय से काम कर रही हैं और तीनों एएसपी के पास स्थायी कार्यालय तक नहीं है।

अगस्त में हो सकती है घोषणा

रायपुर के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे जिले में एक समान पुलिस व्यवस्था की मांग की है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री विजय शर्मा भी पूरे जिले में कमिश्नरी के पक्ष में हैं और मुख्यमंत्री स्तर पर सहमति बन चुकी है। शासन अगस्त तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकता है।

बालोद में बड़ा हादसा, बिजली पोल से टकराई कार, इंजीनियरिंग छात्रा की मौत

नई दृष्टिबिंदु / बालोद

जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई। दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में कार सवार पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। हादसा दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के हिंदू होटल के पास हुआ।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि डौंडी नगर पंचायत के बंधियापारा निवासी रंजीत सिंह पाटिल अपने परिवार के साथ ग्राम चिपरा में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 21 वर्षीय शारदा पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई। शारदा बिलासपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थीं और अपनी बुआ की शादी में शामिल होने घर आई थीं। हादसे से परिवार में मातम का माहौल है। घटना के बाद डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं।

अभिनेत्री चुने जाने के बाद यामी गौतम ने कही ये बात

अभिनेत्री यामी गौतम को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। उन्हें फिल्म 'आर्टिकल 370' में बेहतरीन अदाकारी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उनकी फिल्म 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस कामयाबी से अभिनेत्री खुश हैं। पुरस्कार मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है।

खास है पल

अभिनेत्री ने पुरस्कार मिलने के बाद एक्स पर लिखा 'हर सफर में एक ऐसा पल आता है, जो आपको याद दिलाता है कि आपने हार क्यों नहीं मानी। आज मेरे लिए वही पल है। 'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना मेरे लिए एक ऐसा सम्मान है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी।'

ईमानदारी से काम किया

उन्होंने आगे लिखा 'चौदह वर्षों से, मैंने बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहने, ईमानदारी से काम करने और अपनी परफॉर्मेंस को ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। यह सम्मान उम्मीद, हिम्मत, मजबूती और सिनेमा के लिए अटूट प्यार से भरे सफर का नतीजा लगता है। यह एक ऐसा सपना है, जिसे मैंने वर्षों से अपने दिल में संजोकर रखा था और आज, मैं इसे बहुत आभार और विनम्रता के साथ स्वीकार कर रही हूं।'

यामी ने जताया आभार

उन्होंने फिल्म 'आर्टिकल 370' को चुनने के लिए और इसे पुरस्कार देने के लिए आभार जताया है। उन्होंने लिखा 'मेरे परिवार, मेरी टीम, मेरे शुभचिंतकों और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उतार-चढ़ाव के हर दौर में मुझ पर भरोसा किया। आपके भरोसे ने मुझे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी, तब भी जब मंजिल बहुत दूर लगती थी।'

'गजरा' में सच्ची घटना पर आधारित किरदार निभाएंगी अदा शर्मा

हिंदी, तेलुगु और अन्य भाषाओं की फिल्मों में दमदार पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा इन दिनों अपनी नई मराठी फिल्म 'गजरा' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म के जरिए वह पहली बार मराठी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। उनकी यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस पर अदा का कहना है कि जब किसी वास्तविक घटना को बड़े पर्दे पर उतारा जाता है, तो कलाकार और फिल्म निर्माता दोनों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी कहानियों का उद्देश्य उन लोगों के दर्द और संघर्ष को लोगों तक पहुंचाना होता है। बातचीत के दौरान अदा शर्मा ने सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों को लेकर अपनी राय खुलकर साझा की। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के वास्तविक अनुभव या दर्द को पर्दे पर दिखाया जाता है, तो उस कहानी के साथ संवेदनशीलता बरतना बेहद जरूरी होता है। दर्शकों पर असर डालने के लिए किसी की पीड़ा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना सही तरीका नहीं है। अदा ने कहा, ''जब आप वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कोई कहानी बताते हैं, तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमारा मकसद लोगों को चौंकाना नहीं होता, बल्कि उन्हें यह समझाना होता है कि कहानी के किरदार किन परिस्थितियों और भावनाओं से गुजर रहे हैं। अगर दर्शक किसी किरदार के दर्द और भावनाओं को महसूस कर पाते हैं, तभी ऐसी कहानी अपने उद्देश्य में सफल मानी जा सकती है।''

अभिनेत्री ने आगे कहा, ''एक अभिनेता के तौर पर हम किसी और की जिंदगी में कुछ समय के लिए मेहमान बनते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों को जितना हो सके, उतनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पर्दे पर पेश करें।'' अदा शर्मा ने कहा, ''कई बार वास्तविक जिंदगी में होने वाली घटनाएं फिल्मों से भी ज्यादा नाटकीय होती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि फिल्मों में कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत कुछ जोड़ा जाता है, लेकिन सच्ची घटनियों पर आधारित फिल्मों में कई बार ठीक इसका उल्टा करना पड़ता है।'' बता दें कि 'गजरा' फिल्म का निर्देशन श्रेयस जाधव कर रहे हैं। फिल्म की कहानी और विषय को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। निर्माताओं के अनुसार, 'गजरा' साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रियलिटी शो में दिखता है कलाकार का असली चेहरा

टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह 'बिग बॉस 18' में नजर आने के बाद काफी सुर्खियों में रही हैं। अब उन्होंने रियलिटी शो और एक्टिंग की दुनिया के बीच के फर्क को लेकर अपनी राय साझा की है। उनका मानना है कि रियलिटी शो कलाकार के असली स्वभाव को समझने का मौका देते हैं। जब कोई कलाकार रियलिटी शो में आता है तो दर्शक उसे उसके निभाए किरदारों से अलग एक इंसान के रूप में जान पाते हैं। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में ईशा सिंह से जब पूछा गया कि क्या रियलिटी शो किसी अभिनेता या अभिनेत्री को ज्यादा लोकप्रिय बनाने में मदद करते हैं, इस पर उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि इससे किसी कलाकार की लोकप्रियता कितनी बढ़ती है, लेकिन दर्शकों को अपने पसंदीदा सितारों की निजी जिंदगी के बारे में जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। लोग बिहाइंड द सीन्स जैसी चीजें इसलिए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे कलाकार को और करीब से जानना चाहते हैं। जब कोई कलाकार किसी रियलिटी शो में आता है तो दर्शकों को उसके असली स्वभाव, व्यवहार और पसंद-नापसंद को समझने का मौका मिलता है।'' अभिनेत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, ''दर्शक मेरे निभाए किरदारों जैसे जुही और सैयम को जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ईशा कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है और वह किस तरह की इंसान हैं, यह जानने का मौका रियलिटी शो से ही मिलता है। रियलिटी शो में कोई किरदार नहीं होता और न ही कोई अभिनय का पर्दा होता है, बल्कि वहां कलाकार खुद के रूप में सामने आता है।''

मंटो ने मुश्किल दौर से बाहर निकाला

रिजेक्शन पर कही ये बात

रसिका दुगल ने गहरे और हटकर किरदारों को चुनकर अपना करियर बनाया है। लेकिन वह मानती हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका करियर किस दिशा में जा रहा है। जहां 'मिर्जापुर' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं रसिका का कहना है कि 'मंटो' ने उन्हें उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकाला। रसिका ने उन किरदारों के बारे में बात की जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। 'मंटो' ऐसे समय में मिली, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इंडिया टुडे के साथ बातचीत में अपने करियर के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए रसिका ने कहा कि 'मिर्जापुर' बेशक सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंची। लेकिन 'मंटो' ऐसे समय में मिली जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लोगों ने मुझे एक अलग नजरिए से देखा और जो बहुत बड़े दर्शकों तक पहुंचा, वह निश्चित रूप से 'मिर्जापुर' था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज ने मुझे उस मुश्किल दौर से बाहर निकाला, वह 'मंटो' थी। 'किस्सा' और 'मंटो' के बीच सच में एक लंबा गैप था और मुझे ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। उस समय मुझे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जो बहुत मुश्किल था। वह सच में ऐसा दौर था जब मुझे लगता था, 'अब यहां से आगे क्या? अब मैं कहां जाऊं? किस दरवाजे पर दस्तक दूं और किससे पूछूं?' इंडस्ट्री में दो दशक से ज्यादा समय बिताने के बावजूद रासिका कहती हैं कि उन्होंने कभी भी ऑडिशन देने को अपने स्तर से नीचे नहीं समझा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं ऑडिशन दूंगी। पिछले कुछ साल में लोगों ने मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर वे कहते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खुशी-खुशी ऐसा करूंगी क्योंकि इससे मुझे और उन्हें उस रोल में मुझे देखने का मौका मिलता है। मुझे यह जानने का भी मौका मिलता है कि वे क्या चाहते हैं। तो यह दोनों के लिए फायदेमंद है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

खुशकिस्मत हूं की टाइपकास्ट नहीं हुई

रसिका का कहना है कि वह खुशकिस्मत रहीं कि एक ही तरह के किरदारों में बंधकर नहीं रह गईं। 'मिर्जापुर' में एक्टर्स को उनके किरदारों के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं लकी थी क्योंकि 'मंटो', 'मिर्जापुर' और 'दिल्ली क्राइम' लगभग एक ही समय पर रिलीज हुए थे। 'दिल्ली क्राइम' और 'मिर्जापुर' में बिल्कुल अलग-अलग किरदार थे। इसलिए मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे उस विविधता को आजमाने और दिखाने का मौका मिला। दोनों ने अपने-अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 'दिल्ली क्राइम' एक बहुत ही शानदार शो है। रसिका ने माना कि टाइपकास्टिंग से बचना हमेशा उनकी प्राथमिकता नहीं थी।

आर्टिकल 370' को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर आदित्य धर ने जताई खुशी

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं के नाम से पर्दा हट गया है। बीते दिन पुरस्कारों का एलान हुआ। यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा फिल्म ने दो और पुरस्कार जीते हैं। इसी फिल्म के लिए यामी गौतम के नाम का एलान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए शशवत सचदेव ने पुरस्कार जीता है। इस पर आदित्य धर ने रिएक्शन दिया है।

आदित्य धर ने जताई खुशी

बता दें कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साल 2024 के लिए प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं का एलान हो चुका है। 'आर्टिकल 370' को तीन पुरस्कार मिलने पर आदित्य धर गदगद हैं। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है। 'धुरंधर' डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर खुशी जताई है और यह वादा किया है कि वे इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे।

शब्दों में बयां करना मुश्किल

आदित्य धर ने लिखा है, 'फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए तीन नेशनल अवॉर्ड जीतना एक ऐसा पल है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह अनुभव मुझे विनम्र और भावुक बनाता है और मेरा दिल गहरे आभार से भर देता है। जब हमने यह फिल्म बनाने का फैसला किया, तो हमारा मकसद अवॉर्ड पाना नहीं था। हम ईमानदारी, हिम्मत और सच्चाई के साथ एक कहानी कहने के पक्के इरादे से प्रेरित थे। यह देखना वाकई बहुत सुखद है कि देश भर के दर्शकों ने इस सफर को पसंद किया और अब इसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है।

यामी और प्रियामणि के अभिनय को सराहा

इस शानदार सम्मान के लिए सम्मानित जूरी का और उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 'आर्टिकल 370' देखी, उसे सपोर्ट किया, उस पर चर्चा की और उसमें भरोसा जताया। आपके प्यार ने इस फिल्म को स्क्रीन से परे एक नई जिंदगी दी। यह सम्मान हमारे बेहतरीन डायरेक्टर, आदित्य सुहास जांभले का है, जिनकी सोच और पक्के इरादे ने हर फ्रेम को आकार दिया। यामी गौतम और प्रियामणि का भी शुक्रिया, जिन्होंने अपनी एक्टिंग में इतनी गहराई, मजबूती और सच्चाई दिखाई। शाश्वत सचदेव का भी धन्यवाद, जिनका संगीत हमारी कहानी कहने की कला की जान बन गया। हमारी कास्ट और क्रू के हर सदस्य का भी शुक्रिया, जिनकी लगातार मेहनत, जुनून और भरोसे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया'।

ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे

आदित्य ने आगे लिखा है, 'जियो स्टूडियोज में हमारे पार्टनर्स, खासकर ज्योति देशपांडे का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अटूट भरोसे के साथ इस फिल्म का साथ दिया और सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दिया। पुरस्कार मिलना खुशी तो है ही, साथ ही वे आगे की जिम्मेदारी की याद भी दिलाते हैं। यह सम्मान हमारे इस भरोसे को और मजबूत करता है कि ईमानदारी, पक्के इरादे और मकसद के साथ कही गई कहानियां हमेशा अपनी जगह बना ही लेती हैं। यह मंजिल नहीं है। यह एक वादा है कि हम नई सीमाएं तय करते रहेंगे, ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे, जो मायने रखती हैं और ऐसा सिनेमा बनाते रहेंगे जो बातचीत शुरू करे। भावनाओं को जगाए और एक गहरी छाप छोड़े। दिल की गहराइयों से... धन्यवाद। यह सम्मान हम सभी का है। जय हिंद'।

डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, एग्रीस्टेक पंजीयन में लाएं प्रगति : कलेक्टर

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सेवा सेतु पोर्टल एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की सेवाओं के संबंध में सीएससी संचालकों और आधार संचालकों की ली समीक्षा बैठक

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने विगत दिवस को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सेवा सेतु पोर्टल एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की सेवाओं के संबंध में सीएससी संचालकों एवं आधार संचालकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति, आधार अपडेट कार्य तथा एग्रीस्टेक पंजीयन अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई।

कलेक्टर प्रजापति ने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के जरिए नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य शासन का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक तक शीघ्र एवं प्रभावी रूप से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सभी सीएससी संचालक नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तथा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें।

कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने बैठक में उपस्थित सभी सीएससी संचालकों एवं आधार संचालकों को निर्देशित किया कि किसी भी आवेदन को भरते समय संबंधित दस्तावेजों का भली-भांति परीक्षण करें तथा त्रुटिरहित दस्तावेज ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने कहा कि लापरवाही अथवा छोटी-सी त्रुटि के कारण आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक आवेदन पूरी सावधानी एवं जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाए। उन्होंने अपूर्ण दस्तावेज स्वीकार नहीं

करने, आवेदकों को आवश्यक जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कलेक्टर प्रजापति ने जिले में आधार अपडेट की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट, एमबीयू के माध्यम से आधार अपडेशन, बायोमेट्रिक एवं जनसांख्यिकीय जानकारी के अद्यतन सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आधार सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा पात्र हितग्राहियों के आधार अपडेट का कार्य प्राथमिकता के साथ समय पर पूर्ण किया जाए। साथ ही आधार केंद्रों पर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान कलेक्टर प्रजापति ने एग्रीस्टेक पंजीयन की भी समीक्षा की। उन्होंने सीएससी संचालकों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए प्रगति लाने कहा। उन्होंने कहा कि किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन के लाभों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाए तथा पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं सीएससी संचालकों को आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य अनुरूप कार्य करते हुए शासन की डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर प्रजापति ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा सेतु प्रबंधकों को प्रशस्ति-पत्र एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए सभी को प्रेरित किया। बैठक में अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य सहित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के संबंधित अधिकारी, सीएससी संचालक, आधार संचालक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

खास खबर

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : ग्राम पंचायत करमरी के सरपंच दीनदयाल के घर का बिजली बिल हुआ शून्य

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण परिवारों के लिए न केवल बिजली बिल से राहत का माध्यम बन रही है, बल्कि अतिरिक्त आय का भी नया स्रोत बनकर उभर रही है। जिले के छुरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत करमरी के सरपंच दीनदयाल साहू ने अपने घर के छत पर सोलर पैनल के माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा अपनाकर बिजली बिल शून्य कर लिया है। सरपंच दीनदयाल साहू ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी जनपद पंचायत छुरिया के माध्यम से प्राप्त हुई। योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अधिकृत वेंडर से संपर्क कर योजना के सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि संयंत्र की कुल लागत लगभग 1 लाख 90 हजार रूपए आई, जिसके लिए उन्होंने ग्रामीण बैंक करमरी से ऋण प्राप्त किया। संयंत्र स्थापित होने के बाद उन्हें शासन से 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे आर्थिक भार काफी कम हो गया। सरपंच साहू ने बताया कि सोलर संयंत्र लगने से पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 1200 से 1500 रूपए तक आता था, लेकिन अब उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि उनके घर में बिजली की खपत अपेक्षाकृत कम है, जबकि 3 किलोवाट संयंत्र से पर्याप्त बिजली का उत्पादन हो रहा है। अतिरिक्त बिजली विद्युत ग्रिड में भेजी जा रही है, जिसके बदले उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 4500 से 4600 रूपए की अतिरिक्त आय बिजली विभाग से प्राप्त होगी।

सरपंच दीनदलया साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ देखकर ग्राम पंचायत करमरी के अनेक ग्रामीण भी अपने घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इससे न केवल उनका बिजली बिल कम होगा, बल्कि भविष्य में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। साहू ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति अपना अभार व्यक्त किया।

कवर्धा में नि :शुल्क कैंसर जांच और परामर्श शिविर में 33 लोगों ने कराया अपना स्वास्थ्य परीक्षण

कवर्धा। जिला अस्पताल कवर्धा में निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार जिले में प्रतिमाह कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन को समय पर कैंसर की जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो सके। शिविर में नया रायपुर स्थित बालको मेडिकल सेंटर के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. मुरली मोहन पीके (ऑन्को सर्जन) एवं उनकी टीम ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कीं। जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए कुल 33 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

शिविर के दौरान महिलाओं के लिए मेमोग्राफी के माध्यम से स्तन कैंसर की जांच, पेप स्मीयर के जरिए बच्चेदानी के मुख (सर्वाइकल) कैंसर की जांच तथा ब्रश साइटोलॉजी के माध्यम से मुख कैंसर की जांच जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। जांच के दौरान 7 संभावित मरीजों की पहचान की गई, जिन्हें आवश्यक परामर्श देकर आगे की उपचार प्रक्रिया से जोड़ा गया तथा नियमित फॉलोअप की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। शिविर में 2 महिलाओं की मेमोग्राफी, 5 महिलाओं की पेप स्मीयर जांच की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि स्तन में गांठ, मुंह में लंबे समय तक रहने वाला अल्सर, लगातार खांसी, अत्यधिक थकान, बिना कारण वजन कम होना, खून की कमी, गले में गांठ, निगलने में कठिनाई तथा असामान्य रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए। समय पर जांच और उपचार से कैंसर पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें तथा प्रतिमाह आयोजित होने वाले निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

श्रावण महोत्सव : कलेक्टर वर्मा ने भोरमदेव मंदिर परिसर में तैयारियों को लेकर की बैठक

3 अगस्त को बूढ़ा महादेव से भोरमदेव तक निकलेगी भव्य पदयात्रा

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

ऐतिहासिक एवं धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावण महोत्सव और मेले की तैयारियां अब मैदानी स्तर पर तेज हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूरे श्रावण माह को भव्य, सुव्यवस्थित एवं जनसहभागिता आधारित स्वरूप देने के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने भोरमदेव मंदिर परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विशेष रूप से 03 अगस्त को श्रावण मास के प्रथम सोमवार को बूढ़ा महादेव मंदिर से बाबा भोरमदेव मंदिर तक प्रस्तावित भव्य पदयात्रा को लेकर मार्ग में सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पदयात्रा मार्ग से जुड़े सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक सहयोग के लिए दिशा निर्देश देने के लिए कहा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर ने पदयात्रा मार्ग का व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों के किनारे शोल्डर पर जलभराव रोकने के लिए आवश्यक कार्य तत्काल किए जाएं। मार्ग के किनारे रखी भवन निर्माण सामग्री को हटाकर आवागमन सुगम बनाया जाए तथा पूरे मार्ग में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे रात्रिकालीन आवागमन भी सुरक्षित रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस और आबकारी टीम को लगातार गश्त और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

बैठक में मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर वर्मा ने मंदिर परिसर में स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, सीसीटीवी निगरानी तथा श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े सभी तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में लोकचंद साहू, आदित्य श्रीवास्तव, एसडीएम सागर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी एफआर वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद तिवारी, तहसीलदार हुलेश्वर पटेल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी उपस्थित थे।

कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए हो सभी जरूरी सुविधाएं

कलेक्टर ने कहा कि 03 अगस्त की पदयात्रा केवल एक दिवसीय आयोजन नहीं, बल्कि पूरे श्रावण माह में बाबा भोरमदेव आने वाले हजारों श्रद्धालुओं एवं कांवड़ यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समय पूर्व आवश्यक तैयारियां पूरी करें, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रावण माह के दौरान किसी भी व्यवस्था में कमी न रहे और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण एवं सतत मॉनिटरिंग की जाए, जिससे भोरमदेव श्रावण महोत्सव का आयोजन श्रद्धालुओं के लिए सहज, सुरक्षित और यादगार बन सके।

भावना बोहरा ने इन्दौरी क्षेत्र में विकास कार्यों का किया भूमिपूजन व लोकार्पण

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधायक भावना बोहरा ने मंगलवार को इन्दौरी क्षेत्र के ग्राम कोसमंदा, झिरौनी और केसली में 1 करोड़ 07 लाख 19 रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दो गौरव पथ, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, भूमि समतलीकरण, शिव मंदिर जीर्णोद्धार सहित विभिन्न जनहितकारी निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया तथा प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण किया। विधायक भावना बोहरा द्वारा इन विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा, सामाजिक अधोसंरचना, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा ग्रामीण जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। क्षेत्रवासियों ने विधायक भावना बोहरा का स्वागत करते हुए इन विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि इन निर्माण कार्यों से गांवों के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं आधारभूत विकास को नई दिशा मिलेगी।

विधायक भावना बोहरा ने ग्राम कोसमंदा में सीसी रोड और नाली निर्माण सहित 31 लाख 17 हजार एवं 23 लाख 3 हजार की लागत से निर्मित होने वाले दो गौरव पथ, 16 लाख रुपए की लागत से गौठान व स्कूल का समतलीकरण, 5 लाख रुपए की लागत से शनि मंदिर का जीर्णोद्धार तथा ग्राम झिरौनी में 11 लाख 69 हजार रुपए की लागत से आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम केसली में 20 लाख 30 हजार रुपए की लागत से निर्मित शासकीय प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास ही विकसित पंडरिया की आधारशिला है। गांव तभी आगे बढ़ेंगे जब वहां मजबूत सड़कें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर सामाजिक अधोसंरचना और सांस्कृतिक-धार्मिक स्थलों का संरक्षण समान रूप से सुनिश्चित होगा। गांवों में बनने वाले गौरव पथ आवागमन को सुगम बनाकर स्थानीय विकास को नई गति देंगे। वहीं आंगनबाड़ी भवन के निर्माण से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा वातावरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण हमारी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। कुछ ही दिनों में सावन माह शुरू होने वाला है और शिव मंदिर के जीर्णोद्धार से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और गांवों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान और सशक्त होगी।

खैरागढ़ में वकील दंपती सामाजिक बहिष्कार का झेल रहा दंश, एसपी से शिकायत

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

कानून की किताबों में लोगों को उनके अधिकार बताने वाला एक वकील दंपती अब खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने पुलिस के दरवाजे तक पहुंचा है। खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम देवरी में अंतरजातीय विवाह को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है।

अधिवक्ता नेमीचंद वर्मा और उनकी पत्नी प्रमिला सोनकर ने समाज के कुछ कथित पदाधिकारियों पर सामाजिक बहिष्कार, 35 हजार रुपये की अवैध वसूली, जबरन सामूहिक भोज कराने और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज करने की

मांग की है। पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ को सौंपे गए आवेदन में नेमीचंद वर्मा ने बताया है कि उन्होंने सितंबर 2025 में अपनी इच्छा से प्रमिला सोनकर से विधिसम्मत विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद गांव में समाज की बैठक बुलाई गई, जिसमें कथित तौर पर यह फैसला सुनाया गया कि अंतरजातीय विवाह करने के कारण उनके परिवार पर 35 हजार रुपये का सामाजिक जुर्माना लगाया जाता है।

शिकायत के मुताबिक उस समय उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। बाद में परिवार ने समाज के दबाव में यह राशि जमा कर दी, लेकिन इसके बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि उनसे पूरे समाज के लिए सामूहिक भोज कराने और समाज की आराध्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना करने के लिए भी कहा गया। सामाजिक बहिष्कार खत्म होने की उम्मीद में परिवार ने यह सब भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें और उनकी पत्नी को समाज में दोबारा शामिल नहीं किया गया।

शिकायत में सुकरीत वर्मा, कोदू वर्मा, समय लाल वर्मा, जैत वर्मा और चंद्रबहादुर वर्मा को आरोपी बनाया गया है। अधिवक्ता दंपती ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, कथित रूप से वसूले गए 35 हजार रुपये वापस दिलाया जाए और समाज के नाम पर लोगों को सामाजिक दंड देने की पूरी व्यवस्था की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

कानून का कड़ा पहरा

बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और ट्रिपल सवारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई, अभिभावकों को भी दी गई कड़ी चेतावनी

स्कूलों के बाहर नाबालिग वाहन चालकों पर यातायात पुलिस और आरटीओ का बड़ा एक्शन

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

बेमेतरा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह स्कूल खुलने के समय निजी स्कूलों के बाहर विशेष जांच अभियान चलाकर नाबालिग वाहन चालकों, ट्रिपल सवारी, बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई।

बेमेतरा जिले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यातायात पुलिस और परिवहन विभाग (आरटीओ) की संयुक्त टीम ने सुबह निजी स्कूलों के बाहर सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे छात्र मिले जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट और ट्रिपल सवारी करते हुए दोपहिया वाहन से स्कूल पहुंचे थे।

संयुक्त टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए अभिभावकों से भी अपील की कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें।

यातायात पुलिस का कहना है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनकी और अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। इसी को देखते हुए जिले में आगे भी ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे।

"प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और उन्हें बिना लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति न दें।"

केएल मोहर, आरटीओ अधिकारी बेमेतरा

बेमेतरा शहर की पहचान टूटी नालियां और सड़क पर फैला हुआ कूड़ा-करकट

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

वार्ड नंबर 14 बेमेतरा में सार्वजनिक शौचालय से लगा हुआ गार्डन और तालाब, रोड से लगी हुई टूटी हुई नाली, आसपास लगा मलबे कचरे का ढ़ेर, स्वच्छ साफ, सुरक्षित, स्वच्छता की पोल खोल रहा है, गार्डन के अंदर डिस्पोजल पानी पाउच बोतले यह दिखाने के लिए काफी है कि यहां किन लोगों का जमावड़ा है, यही तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जहां बेमेतरा में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं।

वहीं कुछ दिनों के ही बरसात से तालाब के किनारे भरे हुए कचरे यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है, केवल यह एक स्थान की बात नहीं बेमेतरा के कई तालाबों की यही स्थिति है, जहां एक ओर बेमेतरा में सफाई कर्मचारियों की कमी है, वही जनप्रतिनिधि, पार्षद, यहां से रोज गुजरते हैं, यह सब उन्हें क्यों नहीं नजर आता, बरसात में जहां पीने के

लिए स्वच्छ पानी के लिए क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है।

वही ऐसे भरी हुई नालियों और कचरे के ढेर, हैजा ,मलेरिया, डायरिया ,डेंगू आदि बीमारियों को बढ़ाने का कारण बन जाएगी, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी लगातार वाटर हार्वेस्टिंग और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए-नए उद्यम करते रहते हैं, बरसात में फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए जहां जानकारी ही बचाव है, स्वच्छता और सुरक्षा ही बचाव है तो स्वच्छता रखने में जन नेता स्वच्छता पखवाड़े का इंतजार क्यों करते है।

फर्जी दिव्यांग बनकर कर रहे सरकारी नौकरी

हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही प्रमाण पत्रों की जांच

विशेष पड़ताल नई दृष्टिबिंदु

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-मुंगेली

प्रदेश के सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी करने का बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। नई दृष्टिबिंदु की पड़ताल में सामने आया कि स्वस्थ और आंशिक रूप से दिव्यांग लोगों ने डॉक्टरों से साठगांठ कर मेडिकल बोर्ड से ही असली प्रमाण पत्र बनवा लिए। कुछ ने इग्नू और प्रदेश की यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेकर नौकरी हासिल कर ली। शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी और पंचायत विभागों में ऐसे कमर्चारी वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकांश मामलों में जांच और कार्रवाई अधूरी है।

सिस्टम की साठगांठ, जांच से बचने के हथकंडे : मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के इखफल गांव में ग्रामीणों ने दावा किया कि यहां कई लोग पूरी तरह स्वस्थ होने के बावजूद दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। गांव के वार्ड पंच देवी सिंह राजपूत ने कहा, "आप किस तरह के बहरे की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट वाला या असली? किसी को बताना मत, यहां चार जांच हो चुकी हैं। डॉक्टरों से मिलकर प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं।"

इसी तरह सेमरिया, सारधा, सुकली और विचारपुर समेत आसपास के गांवों में भी इसी तरह फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी लेने के आरोप हैं। दिव्यांग संघ के प्रांताध्यक्ष संतोष टीई ने शासन को 127 संदिग्ध कर्मचारियों की सूची सौंपी है। इनमें से 46 लोग जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। इसके बावजूद न जांच पूरी हुई और न दोषियों पर अंतिम कार्रवाई।

बहरेपन का स्वांग और फर्जी बीएड से 127 लोग कर रहे कब्जा

आदेश हुए, कार्रवाई नहीं: दस्तावेज बताते हैं कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही: मई 2023: सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए। अगस्त 2024: मुंगेली कलेक्टर ने संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच, बर्खास्तगी और प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों की जांच के आदेश दिए। जुलाई 2025: 27 कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। जनवरी 2026: कृषि विभाग ने 17 संदिग्ध कर्मचारियों की सूची जिलों को भेजी।

मुंगेली के अपर कलेक्टर जेएल यादव ने कहा, "हाईकोर्ट के आदेश पर स्पेशल टीम बनाई गई थी, लेकिन संबंधित कर्मचारी जांच कराने ही नहीं आ रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती ले जाना संभव नहीं है। आदेश का पालन नहीं करने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।"

अधिकारी क्या बोले : समाज कल्याण विभाग की सचिव शहला निगार का कहना है, "जिन विभागों में दिव्यांगता के आधार पर कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उसकी जांच और कार्रवाई संबंधित विभाग ही करता है। कार्रवाई के बाद विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को अवगत कराया जाता है।"

मुंगेली जिला अस्पताल के तत्कालीन सिविल सर्जन एवं ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. एमके रॉय से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा, "मैं बाहर हूं, बात नहीं कर सकता।" इसके बाद भेजे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया।

हाईकोर्ट के आदेश पर सिर्फ 3 कर्मचारियों ने ही जांच कराई। बाकी या तो मेडिकल लीव पर हैं, या बार-बार तारीख टाल रहे हैं, या कोर्ट के सहारे कार्रवाई रोक रहे हैं। आरक्षण का लाभ जरूरतमंद दिव्यांगों की जगह फर्जी लोगों को मिल रहा है और सिस्टम इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है।

कुछ नमूने, बड़ा घोटाला

1. **कान सामान्य, फिर भी दिव्यांग:** झीली के व्याख्याता अक्षय राजपूत की रायपुर मेडिकल कॉलेज की ईएनटी जांच में दोनों कान सामान्य पाए गए। मई 2023 में कलेक्टर के आदेश के बावजूद न बर्खास्तगी हुई न एफआईआर।
2. **30% दिव्यांगता पर नौकरी:** शिक्षक सुधेश कुमार सिंह बघेल केवल 30% दिव्यांग हैं जबकि सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम 40% जरूरी है। बर्खास्तगी की अनुशंसा के बाद भी कार्रवाई नहीं।
3. **फर्जी बीएड डिग्री:** गौरेला के व्याख्याता अविनाश राठौर की बीएड डिग्री की जांच में इग्नू ने लिखित में बताया कि ऐसा प्रमाण पत्र उनके रिकॉर्ड में कभी जारी ही नहीं हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी मामला लंबित।
4. **नौकरी के साथ रेगुलर पढ़ाई:** किरंदुल की प्राचार्य मागरिता टोप्पो पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के दौरान बस्तर विवि से नियमित बीएड किया और उसी अवधि का सरकारी वेतन भी लिया। विभागीय जांच में अनियमितता के बाद भी पद पर बनी हुई हैं।
5. **जांच से बचने मेडिकल लीव:** ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पूजा पहारे ने हाईकोर्ट के जांच आदेश के बाद मेडिकल कॉलेज में परीक्षण से पहले अवकाश और फिर मेडिकल लीव ले ली।
6. **बिना हियरिंग एड के काम:** कृषि विभाग के आरईओ गुलाब सिंह राजपूत ने भी बहरेपन का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पाई। वे कलेक्टोरेट में पदस्थ हैं और बिना हियरिंग एड के काम करते दिखे।

राज्य में पूर्णत: डिजिटल एफआईआर लागू करने वाला पहला जिला बना दुर्ग

प्रार्थी और विवेचक दोनों करेंगे ई-साइन प्रक्रिया होगी पारदर्शी और पेपरलेस

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्णतः डिजिटल एफआईआर प्रणाली लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। यहां अब विवेचक के साथ-साथ प्रार्थी भी ई-साइन के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा थानों को उपलब्ध कराए गए ए-ढीह्न के जरिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन दुर्ग जिले में किया जा रहा है। वर्तमान में जिले के सभी विवेचक शत-प्रतिशत ई-साइन के माध्यम से प्रथम सूचना पत्र की प्रक्रिया संपादित कर रहे हैं।

भिलाई नगर थाने में हुआ पहला ई-साइन: इसी क्रम में थाना भिलाई नगर में प्रार्थी का पहला ई-साइन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ ही दुर्ग में विवेचक और प्रार्थी दोनों के डिजिटल हस्ताक्षर से एफआईआर की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है।

पारदर्शी और त्वरित होगी प्रक्रिया : पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस डिजिटल तकनीक से एफआईआर पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, त्वरित और नागरिक-अनुकूल बन रही है। पेपरलेस व्यवस्था से डिजिटल अभिलेखों का बेहतर संधारण भी हो सकेगा और नागरिकों को आधुनिक, तकनीक-आधारित पुलिस सेवाएं मिलेंगी। दुर्ग पुलिस ने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवाचार और डिजिटल प्रणालियों का विस्तार लगातार किया जाएगा।

कल महात्मा गांधी कला मंदिर में 'सुमन की आशा' संगीतमय संध्या

आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के सदाबहार गीतों को देंगे सुर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-बीएसपी के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा 24 जुलाई को महात्मा गांधी कला मंदिर, सिविक सेंटर में संगीतमय संध्या 'सुमन की आशा' का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। यह विशेष संध्या भारतीय फिल्म संगीत की दो महान पाश्वर्गायिकाओं पद्मविभूषण आशा भोसले और पद्मभूषण सुमन कल्याणपुर के कालजयी गीतों को समर्पित होगी।

प्रसिद्ध कलाकार देंगे प्रस्तुति : इस अवसर पर अंचल की सुप्रसिद्ध गायिकाएं अंजलि शुक्ला, गौतमी चक्रवर्ती, सुमीता सरकार, अनुष्का पाण्डेय एवं सोमा कश्यप तथा सुप्रसिद्ध गायक चलपति राव और जगमोहन अपनी मधुर आवाज में इन स्वर विभूतियों के गीत प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में 1970 के दशक से लेकर दोनों गायिकाओं के दीर्घ संगीत सफर के लोकप्रिय और सदाबहार फिल्मी गीतों की आकर्षक प्रस्तुति होगी। संध्या को अंचल के अनुभवी और प्रतिष्ठित संगतकार सजीव संगीत से सजाएंगे।

प्रवेश नि:शुल्क : भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में सभी संगीत प्रेमियों एवं सुधी दर्शकों के लिए प्रवेश पूर्णतः नि:शुल्क रहेगा। संयंत्र प्रबंधन ने नगरवासियों और संगीत प्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस सुरमयी संध्या का आनंद लेने का आग्रह किया है।

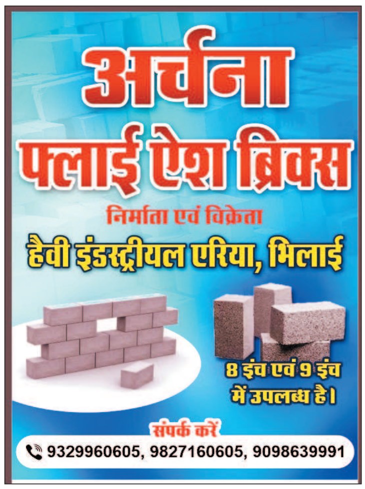

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100